सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 89, नई दिल्ली । सोमवार, 10 जून 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते।

03 NEET UG परीक्षा ने तोडा भरोसा, अब होगा क्या?
06 गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता में फिर प्रवेश कर
08 मोदी सरकार में जेपी नड्डा की हुई वापसी, कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष?

रिठाला-कुंडली मेट्रो की सौगात, मंजूर हुई डीपीआर, डीडीए ने 1000 करोड़ रुपये जारी किए

संजय बाटला

नई दिल्ली। सोनीपत जिले से दिल्ली तक जल्द मेट्रो रेल दौड़ती नजर आएगी। कुंडली व नाथूपुर तक मेट्रो लाइन बिछाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। करीब 12 साल से कागजों में उलझे रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर के निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय के पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड ने प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत छठे कॉरिडोर के लिए निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 1000 करोड़ रुपये के ग्रांट की मंजूरी दे दी है। कुंडली तक मेट्रो आने से सोनीपत से दिल्ली आवागमन करने वाले कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मेट्रो का विस्तार होने से यह दिल्ली के मध्य से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पहला कॉरिडोर होगा। सरकार से मंजूरी मिलने पर प्रदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद व बहादुरगढ़ के बाद प्रदेश में मेट्रो का चौथा विस्तार किया जाएगा। इस समय मेट्रो रेल रेड लाइन पर दिल्ली के रिठाला तक चलाई जा रही है। मेट्रो को रिठाला से नरेला तक लाया जाएगा, वहां से कुंडली के रास्ते नाथूपुर तक मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। रेड लाइन कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन

रिठाला, रोहिणी सेक्टर-25, रोहिणी सेक्टर-26, रोहिणी सेक्टर-31, रोहिणी सेक्टर-32, रोहिणी सेक्टर-36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर-35, रोहिणी सेक्टर-34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3-4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 1-2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनौठ, न्यू सनौठ, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला, नरेला सेक्टर-5, कुंडली और नाथपुर।

नाथूपुर से गाजियाबाद जा सकेंगे लोग

मेट्रो का विस्तार नाथूपुर व कुंडली क्षेत्र को पहले से ही चालू रेड लाइन से जोड़ देगा। यह रेड लाइन मध्य और पूर्वी दिल्ली के महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक जाती है। जिले के लोगों को मेट्रो ट्रेन के जरिए दिल्ली होते हुए गाजियाबाद जाने का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा।

आठ साल पहले मेट्रो के विस्तार का लिया था निर्णय

सोनीपत के लोगों की मांग पर वर्ष 2016 में मेट्रो के विस्तार के चौथे चरण में रिठाला-नरेला-कुंडली रेड लाइन एक्सटेंशन को शामिल किया था। इसकी डीपीआर भी तैयार कराई गई थी, लेकिन बजट जारी नहीं होने के कारण इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ था। रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर 26.463 किलोमीटर का होगा, जिसमें 22 स्टेशन होंगे। इनमें से 21 एलिवेटेड पर बनाए जाएंगे। यह रेड लाइन पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर होगा। इससे गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की तरह हरियाणा का यह हिस्सा भी मेट्रो लाइन के जरिए दिल्ली से सीधे जुड़ सकेगा। मेट्रो लाइट के बजाय मेट्रो चलाई जाएगी

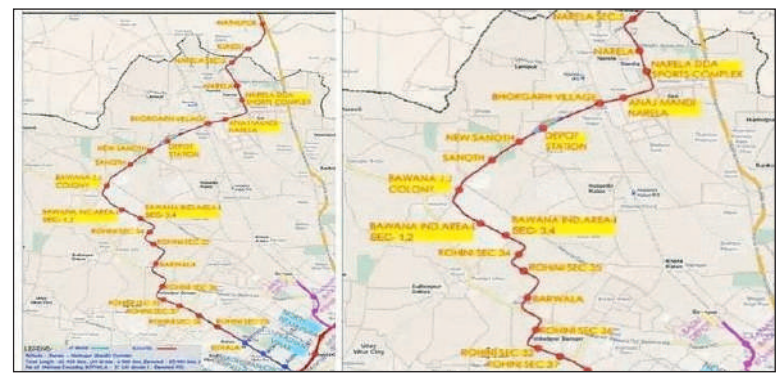

फेज-4 में मेट्रो के तीन निर्माणाधीन कॉरिडोर का काम कोविड के कारण लटका था। पिछले साल डीएमआरसी ने रिठाला-बवाना-नरेला कॉरिडोर को कुंडली तक विस्तार करने के लिए एक नई डीपीआर बनाने का काम शुरू किया था। यह भी तय किया गया है कि इस कॉरिडोर पर मेट्रो लाइट चलाने के बजाय सामान्य मेट्रो ही चलाई जाएगी।

कुंडली तक मेट्रो लाने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो लाइन के लिए डीपीआर मंजूर होने से सोनीपत वासियों के लिए एक तोहफा है। अब इसका निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड ने रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर के डीपीआर को मंजूरी दी है। डीडीए ने कॉरिडोर निर्माण के लिए 1000 करोड़ का बजट जारी किया है। 26.463 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन होंगे। इनमें से 21 एलिवेटेड पर बनाए जाएंगे।

तेजस एक्सप्रेस के डिरेल होने की जांच तेज, स्थानीय अधिकारियों को दिल्ली बुलाया

परिवहन विशेष न्यूज

प्रकरण में शनिवार को पूरे दिन स्थलीय एवं घटना में लापरवाही किस स्तर पर हुई इसकी जांच चलती रही। रेलवे के स्थानीय अधिकारियों को रेल मुख्यालय दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक अधिकारी ने नाम ने छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई पर गाज गिर सकती है।

गाजियाबाद। भुवनेश्वर से नई दिल्ली को जा रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस का एक डिब्बा बी-1 एसी थर्ड शुक्रवार को गाजियाबाद जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार से कुछ दूर पहले तकनीकी खामियों के चलते डिरेल हो गया था। सूत्रों से पता चला है कि इस प्रकरण में शनिवार को पूरे दिन स्थलीय एवं घटना में लापरवाही किस स्तर पर हुई, इसकी जांच चलती रही। रेलवे के स्थानीय अधिकारियों को रेल मुख्यालय दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक अधिकारी ने नाम ने छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार

ट्रैक की स्थलीय जांच के बाद रेलवे के तकनीकी अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। बारीकी से ट्रैक का तकनीकी मुआयना करने पर पाया गया है कि यह हादसा तकनीकी खामी के चलते हुआ है। सूत्रों के अनुसार दूसरे दिन हुई प्रारंभिक जांच में कई अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर कई पर गाज गिर सकती है। इस घटना के बाद प्लेटफार्म नंबर तीन और चार के ट्रैक को ठीक करते हुए रेल संचालन के लिए खोल दिया गया है। पता चला है कि तेजस को रन थ्रू ट्रैक से दिल्ली रवाना किया जाना था लेकिन उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी हुई थी।

प्लेटफार्म नंबर-4 से गुजारने का दिया गया था ग्रीन सिग्नल

इसी के चलते प्लेटफार्म नंबर चार से गुजारने का ग्रीन सिग्नल दिया गया था। यह ट्रैक नई दिल्ली- लखनऊ लाइन का है। जहां पर ट्रेन डिरेल हुई वहां पर बृहस्पतिवार को ही मेंटेनेंस का कार्य किया गया था। इस कार्य के बाद से लेकर तेजस के डिरेल होने तक इस ट्रैक पर कई स्थानीय एवं एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी। इन ट्रेनों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि ट्रैक की मरम्मत होने से तेजस एक्सप्रेस के डिरेल होने से पहले गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन में कोई तकनीकी खामी तो प्रकाश में नहीं आई।

झाड़-फूँस आदि से बाधित है वाहनों के आवागमन का विकल्प

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हम आपका ध्यान रोहिणी सैक्टर-11, केएनके मार्ग स्थित पूरक नाला सेतु (नजफगढ़ ड्रेन) से भगवान महावीर मार्ग, सैक्टर-25 स्थित इस्कॉन मंदिर की ओर जा रहे निरीक्षण रोड़ की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिस पर दिल्ली जल बोर्ड का मलजल उपचार संयंत्र स्थित है।

इस उपचार संयंत्र के एक ओर सैक्टर-25 व दूसरी ओर नाले की सड़क उपर्युक्त निरीक्षण सड़क है जिसके बीच की दूरी लगभग 100-150 मीटर है जहाँ पूर्व समय में वाहनों के आवागमन का विकल्प उपलब्ध था जोकि वर्तमान समय में झाड़-फूँस आदि से बाधित है।

वर्तमान समय में नाला निरीक्षण मार्ग से होकर छोटे वाहन (LMV) केएनके मार्ग व भगवान महावीर मार्ग के बीच आवागमन कर रहे हैं जबकि सैक्टर-11 की ओर से आकर सैक्टर-25 में प्रवेश के लिए वाहनों को भगवान महावीर मार्ग जाकर रिठाला मैट्रो स्टेशन की ओर बाएं मुड़कर नाला सेतु पार कर यू-टर्न लेकर वापिस आकर दाएं मुड़ना पड़ रहा है जोकि अत्यधिक असुविधाजनक व समय लेने वाला मार्ग/रूट है। इस असुविधाजनक रूट समय नष्ट होने से बचने के लिए सैक्टर-25 की ओर बढ़ रहे वाहन नाला निरीक्षण मार्ग से आकर भगवान महावीर मार्ग पर पहुँचते ही दाईं ओर सर्विस लेन में सीएनजी स्टेशन की ओर वाहनों के प्रवाह की विपरीत दिशा (wrong side) में मुड़ जाते हैं। सर्विस लेन में भले ही वाहनों की संख्या व गति कम हो किंतु विपरीत दिशा में गमन से वाहन सवारों को असुविधा होती है व सड़क सुरक्षा प्रभावित रहती है।

उपर्युक्त व समरूप समस्याओं से बचने के लिए सैक्टर-25 स्थित दिल्ली जल बोर्ड मलजल उपचार संयंत्र के सैक्टर-25 छोर व नाले की ओर छोर के बीच लगभग 100-150 मीटर सड़क मार्ग पुनर्स्थापित किए जाने का सुझाव सह निवेदन विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत है महोदय। प्रस्तावित मार्ग व आसपास के क्षेत्र का बुनियादी नक्शा संलग्न है।

विनम्र निवेदन है कि यातायात पुलिस व दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि विभागों के संबंधित अधिकारीगणों को इस सुझाव सह निवेदन पर अविलंब विचार कर प्रस्तावित मार्ग को पुनर्स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की सलाह जारी करें महोदय।

हम आपके आभारी रहेंगे।

पर्यावरण पाठशाला: रामताल कुंड, सुनरख - वृंदावन

हाल ही में मेरी वृंदावन यात्रा में, मुझे सुंदर रामताल का दौरा करने का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते समय, मैंने इसके बारे में अधिक जानने के लिए ब्रज फाउंडेशन की वेबसाइट देखी। इस स्थान की ऐतिहासिक कहानी वास्तव में एक आँख खोलने वाली है और इसे अवश्य पढ़ना और देखना चाहिए।

वृंदावन के इस्कॉन मंदिर से एक किलोमीटर दूर, सुनरख गाँव की सड़क पर स्थित है प्राचीन रामताल। इसे सत्य युग के सुभरी ऋषि का तपस्थली माना जाता है। यहाँ पर हमने मथुरा जिले की सबसे पुरानी पुरातात्विक खोज की है।

यह प्राचीन स्थल लगभग 2700 साल पुराना है। खुदाई के दौरान हमें बड़े ईंटों से बनी एक प्राचीन जल संरचना मिली, जैसा कि उस काल में उपयोग होता था। आगरा के एएसआई विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की और इस स्थल को पुनर्स्थापित करने के ऐतिहासिक प्रयासों के लिए फाउंडेशन की टीम को बधाई दी।

हमने इस स्थल की प्रासंगिकता का अनुमान लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यमुना नदी इस स्थल के निकट बहती थी, इसलिए संभवतः इसे नींव को स्थिरता देने के लिए बनाया गया था।

यह स्थल संयोगवश हमें मिला और हमने खुदाई शुरू की, जब तक कि हम प्राचीन रामताल की दीवारों तक नहीं पहुँच गए। ये दीवारें 10 मीटर गहराई में दबी हुई थीं। सावधानीपूर्वक खुदाई के बाद चार दीवारें (1.5x24x30 मीटर) सबके आश्चर्य के लिए उभरीं। राष्ट्रीय मीडिया जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया आदि ने इस खोज की कवरेज के लिए दौड़ लगाई। और भी अधिक, क्योंकि ईंट की दीवारों के नीचे एक मोटी लोहे की चादर भी मिली। यह एक अजीब खोज थी क्योंकि भारत के किसी अन्य पुरातात्विक स्थल पर, किसी विशाल नागरिक संरचना की नींव के नीचे इस तरह की लोहे की चादर कभी नहीं मिली।

आगंतुकों को हरी-भरी हरियाली के बीच यह प्राचीन स्थल मिलेगा, जो पिछले दो दशकों में वृंदावन में कंक्रीट के जंगल के बीच एक वास्तविक हरा पुरातात्विक स्थल है। रामताल इतना हरा-भरा और सुंदर है कि यहाँ सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक आगंतुकों की धारा रहती है। पहले आगंतुक प्रमुख संत होते हैं जैसे प्रेमानंद जी महाराज और अन्य, जो यहाँ हरे-भरे पेड़ों के नीचे ध्यान करने आते हैं।

जब ब्रज फाउंडेशन ने इस स्थल को पुनर्स्थापित करना शुरू किया, तब केवल दो बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे और घास का एक भी तिनका नहीं था। पूरा क्षेत्र सूखी बंजर भूमि थी। हमारे बागवानी प्रभारी अमित निहुलकर और माली की टीम ने पूरे क्षेत्र को सैकड़ों फूलों के पेड़, हेज, लताओं आदि से इतना सुंदर बना दिया है कि आपको लगेगा कि आप एक जंगल में हैं। यह भावना वृंदावन में चालीस साल पहले बहुत सामान्य थी। अब आपको पूरे वृंदावन में रामताल का मुकाबला कहीं नहीं मिलेगा।

अनुरोध:

इस खूबसूरत स्थल का दौरा करते समय, कृपया इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए सजग रहें। यह एक वाणिज्यिक स्थान नहीं है, बल्कि प्राचीन युग के इतिहास को संजोने और प्राकृतिक सुंदरता को सराहने के लिए है। आइए हम सब मिलकर इसके शांति और गरिमा को बनाए रखें और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।

आपने देखा है किस तरीके से हर एक पेड़, हर एक धरा की अपनी कहानी है। हमारे पास आँखें तो हैं, पर देखने का नजरिया भिन्न होता है। आपसे अनुरोध है कि जब कभी वृंदावन के प्रांगण में आएं, तो अपनी गाड़ियों से उतर कर पैदल चलें। रज को माथे से लगाकर वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए कभी ऐसे रमणीय स्थलों पर भी आकर विश्राम करें।

आध्यात्मिक बातों को जो आपने सुना है, उसे सिर्फ सुने नहीं, अपने जीवन में उतारें। तभी हम वृंदावन धाम की यात्रा को अपने जीवन में स्थापित करके सविचार अर्जित कर पाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे।

पर्यावरण पाठशाला के माध्यम से हम आपको छोटी-छोटी इन बातों से अवगत कराते हैं, जो हमने पर्यावरण से सीखी हैं। ब्रज फाउंडेशन और इस सुंदर रामताल से जुड़े सभी लोगों को साधुवाद, जिन्होंने सुंदर जगह का निर्माण किया और हमें प्रेरणा दी कि निकट भविष्य में हमें सिर्फ वृंदावन ही नहीं, बल्कि अपने आसपास भी इस तरीके के सुंदर स्थानों का निर्माण करना है और उनका रख-रखाव करना है।

डॉ. अंकुर शरण, एक प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और पर्यावरणविद् हैं। वे ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज़ के सह-संस्थापक और प्रबंधन ट्रस्टी हैं। वे परिवहन विशेष के सहयोग से अपने इकोसिस्टम और हेरिटेज वॉक के माध्यम से प्रेरणादायक यात्राओं और कहानियों को प्रदर्शित करते हुए पर्यावरण पाठशाला पर कार्य कर रहे हैं।

indiangreenbuddy@gmail.com

सोमवार से ट्रायल के लिए खोला जाएगा बसई अंडरपास, इन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

बसई के नजदीक द्वारका एक्सप्रेस-वे का अंडरपास सोमवार से ट्रायल के लिए खोला जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। वैसे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की कमी सामने नहीं आएगी। गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण चल रहा है।

गुरुग्राम। गांव बसई के नजदीक द्वारका एक्सप्रेस-वे का अंडरपास सोमवार से ट्रायल के लिए खोला जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अंडरपास का निर्माण बसई फ्लाईओवर, सेक्टर-102, सेक्टर-102ए, 103, 106, धनकोट, बसई, खेड़की माजरा सहित कई इलाकों को द्वारका एक्सप्रेस-वे से सीधे जोड़ने के लिए बनाया गया है। अंडरपास चार लेन की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशक आकाश पहाड़ी का कहना है कि अंडरपास द्वारका एक्सप्रेस-वे का ही हिस्सा है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। सोमवार से ट्रायल के लिए खोला जाएगा। कुछ दिनों तक ट्रायल देखने के बाद यदि किसी भी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई तो स्थायी रूप से खोल दिया जाएगा।

ट्रैफिक का दबाव होगा कम

इससे आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। वैसे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की कमी सामने नहीं आएगी। बता दें कि गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा से लेकर दिल्ली के महिपालपुर में शिवमूर्ति के सामने तक द्वारका एक्सप्रेस-वे का निर्माण चल रहा है। प्रोजेक्ट को गुरुग्राम एवं दिल्ली दो भागों में बांटा गया है।

गुरुग्राम भाग का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन महीने पहले कर चुके हैं। दिल्ली भाग का निर्माण अगले तीन महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है। दिल्ली भाग में केवल टनल के निर्माण पूरा होना बाकी है। इसका निर्माण पूरा होते ही द्वारका एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक का पूरा लोड डाल दिया जाएगा।

इनसाइड

प्रेग्नेंसी में फायदेमंद हो सकता है इमली का सेवन ! आप ही नहीं बच्चा भी रहेगा सेहतमंद

प्रेग्नेंसी के दौरान खट्टी मीठी इमली महिलाओं को बेहद पसंद आती है, ये इमली केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. अक्सर गर्भवती महिलाओं को खट्टी चीजें खाने की इच्छा करती है और इमली खट्टी तथा स्वादिष्ट होने के साथ ही ढेरों पोषक तत्वों से भी भरी होती है, ऐसे में प्रेग्नेंसी के दौरान इसका सेवन बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. प्रेग्नेंसी के समय महिलाओं का खाना डॉक्टर की देखरेख में निर्धारित किया जाता है, ऐसे में किसी एलर्जी या साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक बार डॉक्टर के सलाह भी अवश्य ले लें. इमली में आयरन, नियासिन और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है जो प्रेग्नेंसी में जी मिचलाने से लेकर कब्ज जैसी ढेरों हेल्थ प्रॉब्लम्स से सुरक्षा देती है. आइए जानते हैं, गुणों की खान इमली प्रेग्नेंसी में कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है :

हड्डियों और दांतों को मिलती है मजबूती

मॉम्स जंक्शन डॉट कॉम के मुताबिक इमली में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, प्रोटीन और जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हड्डियों और दातों को मजबूत रखने के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. यह पोषक तत्व इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में तक मदद कर सकते हैं.

कब्ज से मिलेगी राहत

इमली में स्वाद तो होता ही है, साथ ही इसमें मौजूद फाइबर पेट को खुश रखने में भी मदद करता है. प्रेग्नेंसी के दौरान पेट साफ ना होना वजन बढ़ने का कारण बनता है, ऐसे में फाइबर की भरपूर खुराक देने वाली इमली एक स्मार्ट स्नैक ऑप्शन हो सकता है.

बच्चे को पहुंचेगा भरपूर आयरन

बच्चे की अच्छी हेल्थ और सही डिलीवरी में आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके साथ ही इससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है. प्रेग्नेंसी के दौरान इमली आयरन का एक टेस्टी सोर्स हो सकती है.

जी मचलाने से मिलेगी निजात

प्रेग्नेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस और जी मचलाने की समस्या आम है. अचार और दूसरे खट्टे फूड आइटम से बेहतर पोषण से भरी इमली का सेवन पेट को शांत कर उल्टी आने जैसी समस्याओं से बचाव में मदद कर सकता है.

बच्चा बनेगा सेहतमंद

इमली में मौजूद नियासिन बच्चे की सेहत बनाने में एक अहम किरदार बनता है. विटामिन ए, सी और के की पर्याप्त मात्रा पहुंचाने वाली इमली के सेवन से बच्चे की स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम मजबूत बन सकता है.

क्या होता है महिलाओं का रि-करेंट मिसकैरेज ? 1 छोटी सी लापरवाही भी हो सकती घातक, डॉक्टर से जानें चौंकाने वाले कारण

कई महिलाओं को रि-करेंट मिसकैरेज या गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके लक्षणों को पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आमतौर पर प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में ही होता है. अब सवाल है कि आखिर रि-करेंट मिसकैरेज होता क्या है ? कौन से कारण हो सकते हैं जिम्मेदार ? आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में-

गर्भपात यानी मिसकैरेज किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है. डॉक्टर बताती हैं कि प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में ही महिला और भ्रूण का कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो जाता है. ऐसे में मिसकैरेज का दर्द सहन कर पाना काफी मुश्किल हो सकता है. इसलिए कारणों का पता करके डॉक्टर की सलाह से समय पर इलाज कराना जरूरी है. दरअसल, कई महिलाओं को रि-करेंट मिसकैरेज की समस्या का सामना करना पड़ता है. रि-करेंट मिसकैरेज के लक्षणों को पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आमतौर पर प्रेग्नेंसी के शुरुआती दौर में ही होता है. अब सवाल है कि आखिर रि-करेंट मिसकैरेज होता क्या है ? कौन से कारण हो सकते हैं जिम्मेदार ? इन सवालों के बारे में News18 बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा-

क्या होता है रि-करेंट मिसकैरेज

गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा बताती हैं कि, जिन महिलाओं का तीन से अधिक बार 20-21 हफ्ते में गर्भपात हो चुका हो तो उसे रि-करेंट मिसकैरेज कहा जा सकता है. रि-करेंट मिसकैरेज किसी बीमारी या पहले हो चुके गर्भपात के कारण हो सकता है. इसके अलावा भ्रूण के विकास में होने वाली समस्याएं भी इसका कारण बन सकती हैं.

ये 4 कारण भी हो सकते हैं रि-करेंट मिसकैरेज के कारण

शारीरिकः हर महिला का गर्भाशय शारीरिक रूप से अलग होता है जिससे उसके सफल गर्भधारण की संभावना कम और ज्यादा हो सकती है. कई बार गर्भाशय का असामान्य आकार और ग्रीवा का कमजोर होना भी गर्भपात का कारण बन सकता है. गर्भपात सरवाइकल, फाइब्रॉयड, गर्भाशय में चोट या जन्मजात समस्याएं भी गर्भपात के जोखिम को बढ़ा सकती हैं.

ब्लड क्लॉटः कई बार गर्भाशय में होने वाले ब्लड क्लॉट भी गर्भपात का कारण बन सकते हैं. इसे मेडिकल टर्म में एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहा जाता है. इसके अलावा कमजोर इम्यून सिस्टम को भी इसका जिम्मेदार माना जा सकता है.

हार्मोनलः हार्मोनल समस्याएं भी बार-बार होने वाले गर्भपात का कारण बन सकती हैं. शरीर में प्रोजेस्टेरोन की कमी गर्भपात को बढ़ावा दे सकती है. इसके अलावा एलिवेटिड प्रोलेक्टिन, इंसुलिन रेसिसटेंस और थायराइड डिसऑर्डर भी रि-करेंट मिसकैरेज का कारण हो सकते हैं.

बेहद घातक है महिलाओं की ये बीमारी, शर्मिंदगी हंसती-खेलती जिंदगी में घोल देती है जहर, डॉक्टर से समझें 5 शुरुआती लक्षण

आजकल की खराब जीवनशैली में गर्भाशय कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यह तब होता है जब एंडोमेट्रियम (गर्भाशय की अंदरूनी परत) की कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित और बढ़ने लगती हैं. ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप लेती हैं, जो कैंसर का कारण बन जाती है. इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बता रही हैं डॉ. अमृता साहा-

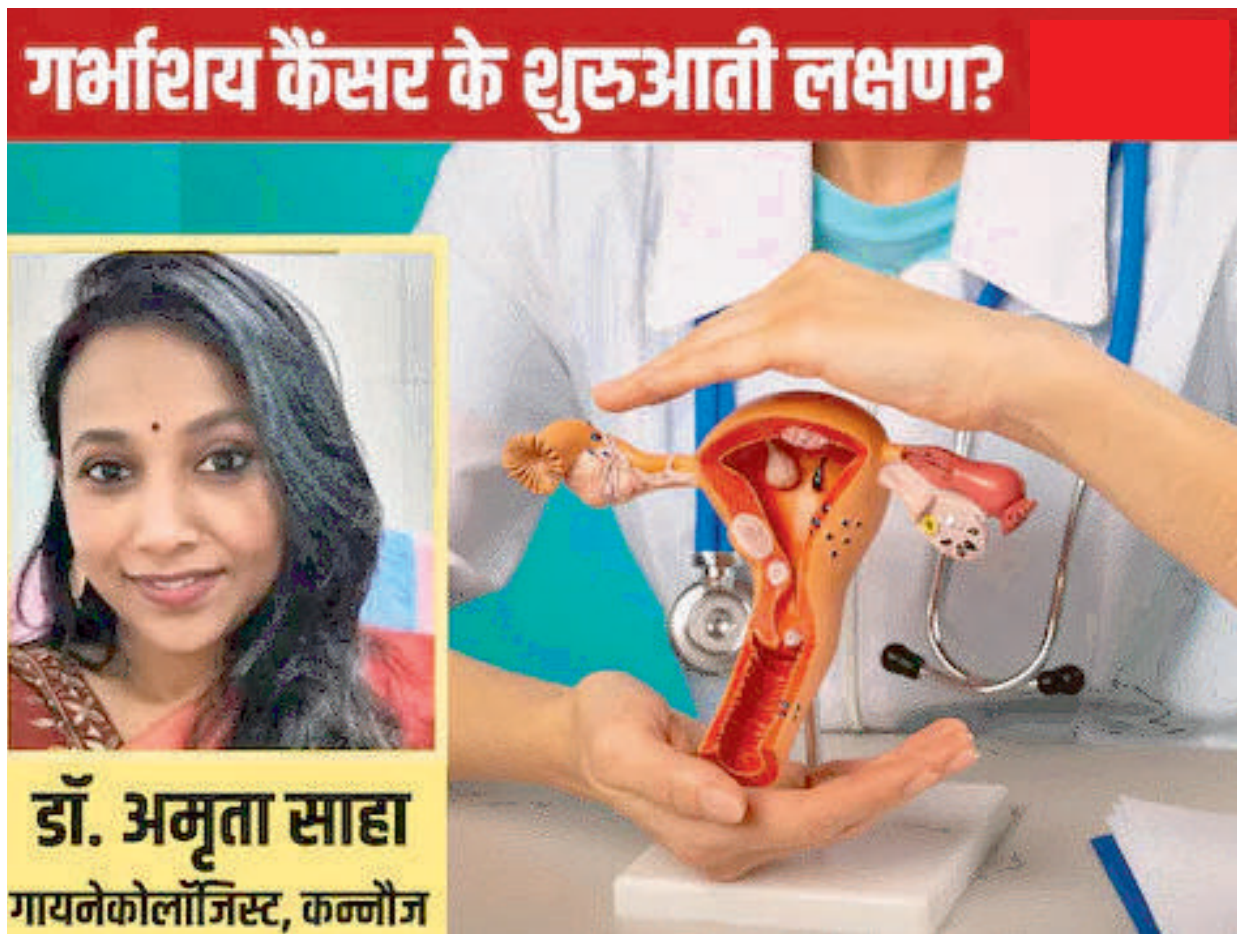

कहने को तो दुनिया तेजी से बदल रही है और महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. अपनी बात को बेबाकी के साथ रखती भी हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी लाखों महिलाएं अपनी बीमारी को छुपाती हैं. लेकिन, क्या आप जानती हैं कि ऐसा करना घातक हो सकता है ? दरअसल, महिलाओं को होने वाली तमाम ऐसी बीमारियां हैं, जिनको इग्नोर करने से उनकी जान भी जा सकती है. गर्भाशय या बच्चेदानी का कैंसर उनमें से एक है. इसको एंडोमेट्रियल कैंसर व यूटेराइन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है. जी हां, गर्भाशय या बच्चेदानी महिलाओं की प्रजनन प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. यही वो स्थान है, जहां गर्भधारण के बाद भ्रूण का विकास होता है. इसलिए बच्चेदानी का स्वस्थ्य होना बेहद जरूरी है.

आजकल की खराब जीवनशैली में गर्भाशय कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यह तब होता है जब एंडोमेट्रियम (गर्भाशय की अंदरूनी परत) की कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित और बढ़ने लगती हैं. ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन जाती है. ऐसे जरूरी है कि शुरुआती लक्षणों को पहचानें. ताकि, समय रहते इलाज कराकर जिंदगी को बचाया जा सके. अब सवाल है कि आखिर गर्भाशय कैंसर के शुरुआती हैं क्या ? इस बारे में News18 को विस्तार से बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा-

बच्चेदानी में कैंसर होने के 5 शुरुआती संकेत

पेट के निचले हिस्से में दर्दः डॉ. अमृता साहा बताती हैं कि, पेट के निचले हिस्से में दर्द और ऐंठन होना बच्चेदानी में कैंसर का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, महिलाओं को श्रोणि में ऐंठन का अनुभव भी हो सकता. अगर आपको बार-बार इस तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए.

ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होनाः यदि किसी महिला को पीरियड्स के अलावा अन्य दिनों में ब्लीडिंग होती है या महीने में कई बार ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, तो इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें. क्योंकि, यह बच्चेदानी में कैंसर का भी लक्षण हो सकता है. इसके प्रति समझदारी दिखाएं और समय रहते डॉक्टर से मिलकर जांच करवाएं.

कई दिन तक पीरियड रहनाः अगर आपके पीरियड्स सामान्य से अधिक दिनों तक चलते हैं, तो यह बच्चेदानी में कैंसर होने का संकेत हो सकता है. इसके अलावा, आपको पीरियड्स के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की परेशानी भी हो सकती है. ऐसी स्थिति में आपको तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए.

मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या डिस्चार्जः मेनोपॉज के बाद महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल ब्लीडिंग की समस्या होना भी बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण हो सकता है. अगर आपको मेनोपॉज के बाद इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाएं ताकि आपका समय पर इलाज किया जा सके.

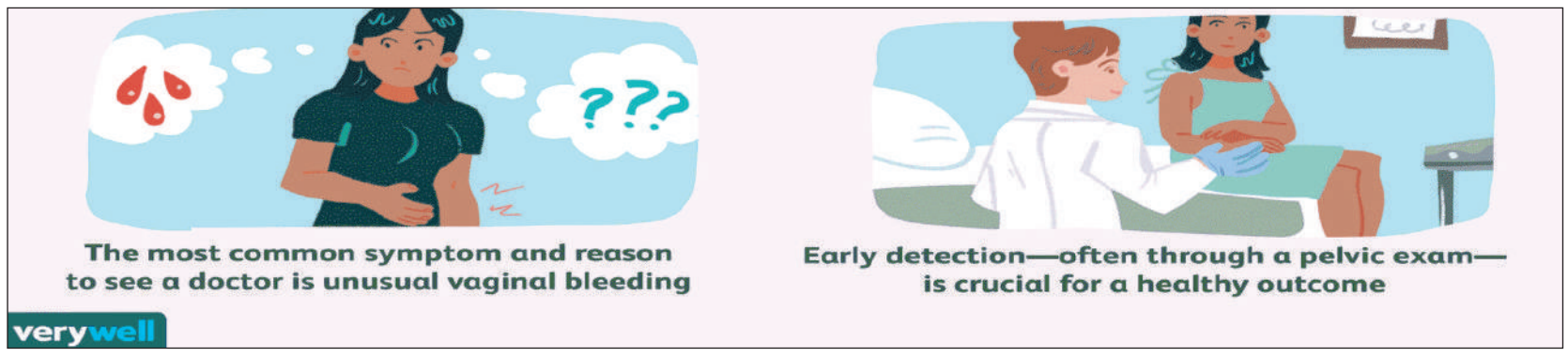

इन 3 आदतों को छोड़ दें महिलाएं, तो हर महीने कर सकती है हजारों रुपये की बचत !

यह पाया गया है कि जब लोग अच्छा कमाते हैं तो सेविंग बढ़ाने की बजाय लोग अपने जीवन का लग्जरी बनाने में अधिक खर्च करने लगते हैं. जिस वजह से बाद में उन्हें दिक्कत आती है और पैसों की जरूरत पड़ने पर उन्हें दूसरों से उधार तक लेना पड़ जाता है. ऐसे में यह जरूरी है कि आप पहले से ही अपने फाइनेंशियल हालात को ध्यान में रखते हुए हर महीने सेविंग जरूर करें. अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा शॉपिंग में खर्च कर देती हैं तो बता दें कि यह आदत आपके लिए आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकती है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप हर महीने सेविंग सेविंग किस तरह कर सकती हैं और किन आदतों में बदलाव लाकर किसी अच्छी जगह उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकती हैं.

बिना लिस्ट के शॉपिंग करना

अक्सर देखा गया है कि महिलाएं सैलरी मिलने के पहले ही दो हफ्ते में इतना अधिक शॉपिंग कर लेती हैं कि महीने का अंत आते आते उनका अकाउंड खाली होने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपना शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उसमें देखें कि सबसे अधिक जरूरी चीज क्या है. इसके बाद देखें कि किन फालतू की चीजों में आपके पैसे खर्च होते हैं. ऐसा करने से आप फलतू खर्च से बची रहेंगी.

मार्केट की बजाय मॉल में खरीददारी

अगर आपको मॉल जाना पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर खरीददारी मॉल से ही करें. बेहतर होगा कि आप अपने आसपास के मार्केट को एक्सप्लोर करें और महीने का सामान, छोटी मोटी चीजें लोकल मार्केट से ही खरीदें. ये सस्ते भी होते हैं और आप इनका जमकर इस्तेमाल भी कर पाएंगी.

महिलाओं के लिए कभी-कभी 'ना' कहना भी जरूरी, जानें किस तरह करें मना

हर महिला चाहती है कि लोग उसे पसंद करें और उसके काम की सराहना हो. कई बार खुद का इमेज बनाए रखने के लिए महिलाएं न चाहते हुए भी उस काम में व्यस्त हो जाती हैं जिस काम को वे नहीं करना चाहती हैं. यही नहीं, महिलाओं की इन आदतों का

- 'मुझसे आपने पूछा इसके लिए थैंक्स लेकिन..
- 'काश मैं आपका काम पूरा कर पाती'.
- 'अगली बार पक्का मैं आपका ही काम पहले पूरा करूंगी'.
- 'मेरे बार में सोचने के लिए थैंक्स लेकिन ये काम मुझे दूसरे का पास करना होगा'.
- 'इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जरूर आपका काम कर दूंगी'.

लोकसभा में क्षेत्र के आधार पर पड़े वोटों के अनुसार आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 18 सीटों पर सिमट जाएगी, जाने ब्यौरा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है. अगर आज दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सत्ता कायम रखना मुश्किल होगा. उसे केवल 18 सीटों पर ही बढ़त मिली है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के साथ ही दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी की कब्जा हो गया है. मगर यह नतीजे तस्वीर का एक ही हिस्सा हैं. **चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में आप के 62 विधायक हैं. इनमें से 44 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से पिछड़ गई.** इससे साफ हो गया कि इस वक्त अगर चुनाव हो गए तो आप को केवल 18 सीटों पर सफलता मिल सकती है. इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी सत्ता पर खतरा पैदा होने की पूर्ण आशंका है. इस तरह देखा जाए तो केवल 18 सीटों पर ही आप के उम्मीदवार आगे रहे. बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार ज्यादातर विधानसभा सीटों पर आगे रहे. इनमें से आप के ज्यादातर बड़े नेता शामिल हैं. जिनमें उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसौदिया समेत कई बड़े नेता शामिल हैं. केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट पर ही आम आदमी पार्टी महज करीब 3 हजार वोटों से ही आगे रहने में कामयाब रही है. मनीष सिसोदिया की

सीट पर तो आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार भाजपा के उम्मीदवार से 29 हजार से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए. वैसे मनीष सिसोदिया भी पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे. आप ने 3 विधायकों को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया था. उनमें **पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार कुलदीप कुमार खुद अपनी ही सीट कोंडली में पिछड़ गए.** उनको करीब 57 हजार और बीजेपी उम्मीदवार को 59 हजार वोट मिले.

उसी तरह **मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती अपनी ही सीट पर बांसुरी स्वराज से पिछड़ गए.** इतना ही मंत्री सौरभ भारद्वाज की सीट पर भी वो पिछड़ गए. केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट पर ही सोमनाथ भारती को मामूली बढ़त मिली थी. पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार महाबल मिश्रा के बेटे द्वारका से विधायक हैं. लोकसभा की सभी 10 सीटों पर आप के विधायक हैं. यहां तक कि **महाबल मिश्रा अपने बेटे विनय मिश्रा की सीट से भी पिछड़ गए.** इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार **कन्हैया कुमार भी बीजेपी के मनोज तिवारी से केवल 4 विधानसभा सीटों पर आगे रहे.** इन नतीजों से साफ है कि अगर आगामी **विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सावधानी के साथ अपने पत्ते चले तो आप के लिए अपनी सत्ता को बनाए रखना कठिन हो सकता है।**

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्विद्यालय से जुड़े स्टार्टअप में तैयार सॉफ्टवेयर किसी भी आयु वर्ग के लिए हो सकता प्रयोग

आप अपने बच्चे या फिर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की एकाग्रता स्तर और बौद्धिक व तार्किक क्षमता जानना चाहे तो अब यह मुमकिन है। इससे आगे सुधार क्षमा पर काम किया जा सकेगा। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) की छात्रा निधि ने ऐसा अनूठा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन करेगा।

दिल्ली। आप अपने बच्चे, या फिर कोई कंपनी अपने कर्मचारी की एकाग्रता स्तर और बौद्धिक व तार्किक क्षमता जानना चाहे तो अब यह मुमकिन है। इससे आगे सुधार क्षमा पर काम किया जा सकेगा। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) की छात्रा निधि ने ऐसा अनूठा सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन करेगा और यह भी बताएगा कि क्षमताओं में कमी कहां है और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर ऑटिज्म, अटेंशन डिफिशिएंट हाईपर एक्टिव डिसआर्डर (एडीएचडी), डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता में सुधार में उम्मीद भी जगा रहा है। निधि के इस स्टार्ट-अप को डीटीयू के अलावा आईआईएम बेंगलुरु व गुजरात सरकार ने अनुदान दिया है।

दिल्ली में कालकाजी एक्सटेंशन में रहने वाली निधि ने 'नीमा एआई' के नाम से बनाए इस स्टार्ट-अप की शुरुआत फरवरी 2022 में की थी। सालभर के भीतर निधि के स्टार्ट-अप की व्यावसायिक क्षेत्र में काफी चर्चा है। निधि का कहना है कि इस समय उनका स्टार्ट-अप केवल बच्चों पर ही के लिए ही है, लेकिन भविष्य में भर्ती प्रक्रिया (प्लेसमेंट/हायरिंग) में भी इस सॉफ्टवेयर के उपयोग करने की योजना है। फिलहाल पूरी टीम बच्चों को लेकर काम कर रही है। स्टार्ट-अप की फाउंडर निधि ने बताया कि उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चों के पढ़ने, सोचने और सीखने की क्षमता व गुंजाइश के बारे में भी बताएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके सॉफ्टवेयर का ऐसे बच्चों के लिए इलाज के तौर पर उपकरण से कोई लेना-देना नहीं है।

40 वर्षों के राजनीतिक तप से गुजर कर मोदी कैबिनेट तक पहुंचे हर्ष मल्होत्रा, जानिए कैसा रहा पूर्वी दिल्ली के सांसद का सफर

परिवहन विशेष न्यूज

एक-एक कदम बढ़ाकर ही व्यक्ति जीवन में मंजिल तक पहुंचता है। भाजपा के साधारण कार्यकर्ता से केंद्रीय राज्य मंत्री बनने तक का हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक सफर ऐसा ही रहा। 40 वर्षों के तप का परिणाम उन्हें इस रूप में मिला है। छात्र रहते हुए युवा कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके वह पार्षद महापौर के जिम्मेदार पद पर रहे।

पूर्वी दिल्ली। एक-एक कदम बढ़ाकर ही व्यक्ति जीवन में मंजिल तक पहुंचता है। भाजपा के साधारण कार्यकर्ता से केंद्रीय राज्य मंत्री बनने तक का हर्ष मल्होत्रा का राजनीतिक सफर ऐसा ही रहा। 40 वर्षों के तप का परिणाम उन्हें इस रूप में मिला है। छात्र रहते हुए युवा कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके वह पार्षद, महापौर के जिम्मेदार पद पर रहे और संगठन में तमाम दायित्वों का निर्वहन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जगह बनाई है। पूर्वी दिल्ली से सांसद बनने वाले वह दूसरे व्यक्ति हैं, जो मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इनसे पहले यह गौरव एचकेएल भगत को प्राप्त हुआ था।

1984 में राजनीति में रखा कदम

हर्ष मल्होत्रा नवीन शाहदरा के एच-ब्लाक में रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। छात्र जीवन के दौरान की हर्ष ने राजनीति की राह पर कदम बढ़ाए थे। वर्ष 1984 में वह यूथ विंग से जुड़े और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का दायित्व संभाला। वर्षों के राजनीतिक संघर्ष से गुजरते हुए वर्ष 2005 में वह भाजपा के नवीन शाहदरा जिले में महामंत्री बनाए गए। वर्ष 2007 में पदोन्नति देते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। दायित्वों के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें जनसेवा के काम में उतारा गया।

कुपोषण के खिलाफ छेड़ी जंग, कंप्यूटर शिक्षा को दी तवज्जो

वर्ष 2012 में उन्हें वेलकम वार्ड से पार्षद का टिकट दिया गया। जीत दर्ज कर वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पार्षद बने। विषयों के प्रति ज्ञान और गंभीरता को देखते हुए उन्हें निगम में शिक्षा समिति के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगातार तीन वर्ष वह इस पद पर रहे। कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने की मुहिम 'सुपोषण' चलाई। इससे करीब 60 हजार बच्चों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा। निगम स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की पहल भी इनकी ओर से की गई थी। वर्ष 2015 में इनको महापौर का दायित्व सौंपा गया था। निगम का मुखिया होने के नाते इन्होंने वेस्ट टू वेल्थ का नारा देते हुए अपशिष्ट प्रबंधन की की परियोजना शुरू की थी। कचरे से बिजली बनाने के काम का आगाज इन्हीं के महापौर रहते हुआ था। वह वर्तमान में भाजपा दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं।

पहली बार में बने सांसद और मंत्री

हर्ष ने पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाया। पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से जीत दर्ज कर वह सांसद बने। पहली बार में ही उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का दायित्व सौंपा गया। पेशे से हर्ष मल्होत्रा उद्यमी हैं। झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में उनकी प्रिंटिंग की इकाई है।

देहदान की मुहिम से जुड़े हैं हर्ष

हर्ष उद्यमी और राजनीतिक फलक से अलग 24 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देह और अंग दान के लिए लोगों को प्रेरित करने की मुहिम के तहत वह काम करते हैं। वह दधीचि देहदान समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वर्तमान में वह इस समिति के अध्यक्ष भी हैं।

दिल्ली में कुछ दिन राहत के बाद फिर पड़ेगी प्रचंड गर्मी, लू को लेकर चार दिन का येलो अलर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

कई दिनों की आंशिक राहत के बाद राजधानी में गर्मी एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। सोमवार से अगले चार दिनों तक लगातार लू वाली गर्मी सताएगी। मौसम विभाग की ओर 10 से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

नई दिल्ली। कई दिनों की आंशिक राहत के बाद राजधानी में गर्मी एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। सोमवार से अगले चार दिनों तक लगातार लू वाली गर्मी सताएगी। मौसम विभाग की ओर 10 से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

गौरतलब है कि बीते सप्ताह दिल्ली के तापमान में कुछ कमी आई थी। शनिवार को तो अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री रहा, लेकिन रविवार से एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री दर्ज किया गया जो अभी के समय में सामान्य है।

कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंच जाएगा। तापमान बढ़ने के साथ तेज गर्म हवाएं भी चलेंगी, जिसके चलते लू का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। खासतौर से खुली जगहों पर लू का असर ज्यादा रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से बृहस्पतिवार तक अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री तक रह सकता है। चार दिन तक दिल्ली में हवा की रफ्तार भी 20 से 30 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है।

दूसरी ओर रविवार को भी दिल्ली का एक्यूआई 200 से नीचे यानी "मध्यम" श्रेणी में रिकार्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एक्यूआइ 180 रहा। इस स्तर की हवा को "मध्यम" श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।

रविवार को दिल्ली में अलग अलग जगहों का तापमान

स्थान	अधिकतम तापमान
नरेला	45.7 डिग्री
नजफगढ़	45.5 डिग्री
पीतमपुरा	44.8 डिग्री
स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स (अक्षरधाम)	44.8 डिग्री
पूसा	44.1 डिग्री

NEET UG परीक्षा ने तोडा भरोसा, अब होगा क्या?

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। जहां एक तरफ भारत सरकार के नए कर्णधार ईमानदारी,सत्य निष्ठा की शपथ ले रहें है, तो वहीं दूसरी ओर सत्य निष्ठा ,कर्तव्य के भारी भरकम शब्दों के नीचे नीट की ली गई परीक्षा के परिणाम को लेकर लेकर सामने आई धांधलियों के बोझ तले दबे लाखों परीक्षार्थी सडकों पर उतर कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट यूजी की परीक्षा को 5 मई,2024 को आयोजित करवाया गया था। लेकिन बरती गई अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका प्रोफेशनल्स टेस्टिंग एजेंसी से कोलकाता हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई और और इस दौरान यांचि चट्टोपाध्याय के अधिवक्ता सुनील राय की तरफ से यहां पर तर्क भी दिया गया कि कुछ परीक्षार्थी जो कि 720 अंक में से 718 या 719नंबर पाए है,जो कि यह अंक अर्जित कर ही नहीं सकतेहैं।

बता दें कि NEET UG,2024 के नतीजे 4 जून को घोषित कर दिया गया था। 67 परीक्षार्थियो को शीर्ष रैक के तहत यानि 720 में से 720 पूरे नंबर दे दिए हैं।दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से पैरवी कर रहे भारत के डिप्टी सालिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी व अधिवक्ता तीर्थपति अचार के तरफ से अक्षत अग्रवाल व अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहां पर उल्लेख किया गया,और इसे न्यायोचित ठहराने का पूरा प्रयास किया गया

था। दोनों बच्चों की दलीलों को सुनकर जस्टिस कौशिक चंदवार जस्टिस अपूर्व सिंह राय के खंडपीठ के माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 10दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का जवाब देने को कहा है।

वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस से भी यहां की गई नीट में जिस तरीके से धांधली हुई है,सुप्रीमकोर्ट की निगरानी में इसकी पूरी जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि पेपर लीक धांधली और भ्रष्टाचारी नेता सहित कई परीक्षाओं में अभिन्न अंग बन गया है।इसकी सीधी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है।परीक्षार्थियों की मांग है कि कठोर स्तर से इस पर जांच हो और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुनः एग्जाम कराया जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस याचिका को दायर कर दिया गया है।कि उत्तर पुस्तिका में एक प्रश्न के उत्तर यहां पर सही थे। और अधिकारियों ने दो सही विकल्प को अंक देकर निष्पक्षता से समझौता कर लिया है।जबकि निर्देशन में यहां पर साफ संकेत दिया गया था।केवल एक विकल्पहीन था।याचि ने प्रश्न करने का फैसला यहां पर किया और 720 में से 633 अंक यानि ने प्राप्त किया।अब याचि का अखिल भारतीय रैंक 44700 के करीब यहां पर था। याचियों की तरफ से कहा गया कि एक अंक उसकी रैंक को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।नीट यूजी का जो एग्जाम जारी हुआ है।रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यार्थी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब एक प्रश्न 4नंबरों का था तो यहां पर परीक्षार्थियों को 720 में 718 व 719 अंक हासिल किया जाना था।लेकिन अभियारथियों ने 718 व 719 अंक पाए है।तो आखिर यह कैसे हो सकता है ? यानि नीट यूजी के रिजल्ट में काफी बडी धांधली इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और इसकी निष्पक्ष तरीके से विपक्षी पार्टियो ने जांच की मांग की है।

118 स्कूलों की CBSE मान्यता समाप्त, बढ़ी विस्तार की तिथि

118 सरकारी सहायता और निजी स्कूलों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो गई है। सीबीएसई ने इसे लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा की इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई है और मान्यता के विस्तार के लिए इन स्कूलों को 19 सितंबर 2023 तक आवेदन करना था।

नई दिल्ली। राजधानी के 118 सरकारी, सहायता और निजी स्कूलों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में इन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो गई है। सीबीएसई ने इसे लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा की इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गई है और मान्यता के विस्तार के लिए इन स्कूलों को 19 सितंबर, 2023 तक आवेदन करना था।

लेकिन वे इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहे। निदेशालय ने कहा कि ये स्कूल के प्रधानाचार्यों और परीक्षा प्रभारी की ओर से घोर लापरवाही को दर्शाता है। निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सीबीएसई ने मान्यता के विस्तार को लेकर आवेदन की तिथि बढ़ाई है।

जिन स्कूलों को मान्यता का विस्तार लेना है वो 30 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर स्कूल इस तारीख तक संबद्धता के विस्तार के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और परीक्षा प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इसके अलावा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों को सीबीएसई संबद्धता की अवधि की जांच करने का निर्देश दिया है। निदेशालय ने कहा कि अगर स्कूल की संबद्धता अवधि 31 मार्च, 2025 तक है, तो वे भी इसमें आवेदन करेंगे।

निदेशालय ने ये भी स्पष्ट किया कि नई संबद्धता, संबद्धता के विस्तार और किसी भी प्रकार के मामले में जुर्माना माफ करने से संबंधित किसी भी फाइल पर परीक्षा शाखा (मुख्यालय) द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त निदेशालय ने सभी जोन के उपशिक्षा निदेशक से अनुरोध किया कि वे इसका अनुपालन सुनिश्चित करें और 25 जून 2024 तक परीक्षा शाखा का उपशिक्षा निदेशक को अनुपालन रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट में स्पष्ट हो कि नई संबद्धता, संबद्धता के विस्तार आदि का कोई मामला लंबित नहीं है।

नोएडा में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ARTO में टेस्ट देने जाने की जरूरत नहीं, बनेंगे दो प्राइवेट सेंटर

परिवहन विशेष न्यूज

एआरटीओ कार्यालय गौतमबुद्धनगर पर प्रतिदिन 200-300 आवेदक पहुंचते हैं। आंकड़ों के आधार पर (वर्ष 2023 में 49482 डीएल बने) कार्यालय पर प्रतिदिन औसतन 135 लाइसेंस बनते हैं। अब इन आवेदकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर भी अब ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और प्रशिक्षण देंगे। जिले में दो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर बनने ड्राइविंग टेस्ट बनने की कवायद शुरू हो गई है।

नोएडा। अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए एआरटीओ में टेस्ट देने जाने की जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर भी अब ड्राइविंग टेस्ट लेंगे और प्रशिक्षण देंगे। जिले में दो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर बनने ड्राइविंग टेस्ट बनने की कवायद शुरू हो गई है।

अगले चार माह में दोनों सेंटरों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। एआरटीओ कार्यालय पर लिए जाने वाले टेस्ट को देने की जरूरत नहीं होगी। अभी लाइसेंस बनवाने के लिए एआरटीओ कार्यालय में टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट व विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही डीएल मिलता है।

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया कि सड़क हादसे कम करने के लिए हल्के व भारी वाहनों को चलाना सिखाकर प्रशिक्षण देकर दक्ष किया जा सके। इसके लिए शासन स्तर से प्राइवेट क्षेत्र में प्रत्यायन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (एडीटीसी) बनाए जा रहे हैं।

58 जिलों में गौतमबुद्ध नगर को भी किया गया शामिल

प्रदेश के 58 जिलों में से गौतमबुद्ध नगर को भी शामिल किया गया है। जिले में दादरी और गौतमबुद्ध नगर में एडीटीसी बनने की दिशा में काम चल रहा है। इनको लेटर आफ इंटेंट दिया जा चुका है। दादरी वाले केंद्र की स्थापना संबंधी काम लगभग पूरा हो चुका है।

इसके भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट बनाकर एआरटीओ विभाग की ओर से शासन को भेजी जा चुकी है। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हालांकि जिले में तीसरा सेंटर भी बनाया जाना है। इसको बनाने की दिशा में काम जारी है।

एक-दो एकड़ में होंगे केंद्र

एआरटीओ ने बताया कि हल्के वाहन के लिए केंद्र बनाने को एक एकड़ जमीन जबकि भारी वाहन के दो एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। इन केंद्रों पर लर्निंग लाइसेंस के प्रशिक्षण के लिए कक्षाओं का संचालन होगा जबकि परमानेंट लाइसेंस पाने को टेस्ट देने के लिए सिमुलेटर और आटोमेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी।

केंद्र प्रबंधक को चालकों को प्रशिक्षण देने के एवज में फीस मिलेगी। इन सेंटरों की मान्यता पांच वर्षों के लिए होगी। इसके बाद इनका रिन्यूअल कराना होगा।

यह होंगे दो केंद्र

1.मेसर्स शिवम मार्बल, रेलवे रोड दादरी, गौतम बुद्ध नगर

2.साईं फायर एप्लाइंसिस प्राइवेट लिमिटेड-गौतमबुद्ध नगर

औसतन प्रतिदिन बनते हैं 135 लाइसेंस

एआरटीओ कार्यालय गौतमबुद्धनगर पर प्रतिदिन 200-300 आवेदक पहुंचते हैं। आंकड़ों के आधार पर (वर्ष 2023 में 49,482 डीएल बने) कार्यालय पर प्रतिदिन औसतन 135 लाइसेंस बनते हैं।

अब इन आवेदकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग की ओर से डीएल बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन की हुई है, लेकिन परमानेंट डीएल के लिए कार्यालय आकर बायोमैट्रिक व फोटो खिंचवाना पड़ता है। अब निजी सेंटर बनने से आवेदकों की पूरी प्रक्रिया होने के बाद आनलाइन डीएल डाउनलोड हो जाएगा और फिजिकल डीएल घर पहुंच जाएगा।

साफ नहीं हुए नाले तो तालाब बन जाएंगी बागू की गलियां, मुश्किल होगा आवागमन

गाजियाबाद में हर साल मानसून सीजन में नालों की सफाई न होने से जलभराव की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। विजयनगर में एनएच-नौ से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन के बायीं तरफ विजयनगर बाइपास के पास बागू क्षेत्र है। यहां पर 20 हजार से अधिक लोगों को हर मानसून सीजन में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है।

गाजियाबाद। शहर में हर साल मानसून सीजन में जलभराव की समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस साल पहले जैसी स्थिति नहीं होगी।

नालों की सफाई का काम समय से शुरू करा दिया गया है, मानसून आने से पहले सभी नाले साफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है, शहर में हर साल बागू की गलियां तालाब बन जाती हैं, इस साल भी आसार ऐसे हैं। यहां पर अब तक नाले की सफाई नहीं हुई है, क्षतिग्रस्त नाले का निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया है।

विजयनगर में एनएच-नौ से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन के बायीं तरफ विजयनगर बाइपास के पास बागू क्षेत्र है। यहां पर 20 हजार से अधिक लोगों को हर मानसून सीजन में जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब एनएच-नौ के चौड़ीकरण का कार्य किया गया तो नाले को तोड़ दिया गया, अब तक यह नाला क्षतिग्रस्त है।

एनएच- नौ की सर्विस लेन पर भर जाता है पानी

जिस कारण न केवल बागू में जलभराव होता है बल्कि एनएच- नौ की सर्विस लेन पर पानी भर जाता है। जिससे नोएडा, दिल्ली की ओर जाने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति बनती है। दैनिक जागरण की टीम ने शनिवार को बागू क्षेत्र में नालों की सफाई की पड़ताल की तो यहां पर स्थिति बदतर मिली।

नाले और नालियों में कूड़ा भरा है, जिससे जलनिकासी बाधित हो रही है। आरोप है कि नगर निगम की टीम द्वारा यहां पर नालों की सफाई का कार्य नहीं कराया गया है। रोजाना नालियों की सफाई में भी लापरवाही होती है, नालियों की सफाई के लिए कर्मचारी कभी-कभी ही यहां पर आते हैं।

ऐसे में लोगों को बदबू और मच्छर की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। एनएच- नौ से सटे नाले की मरम्मत का कार्य अब तक नहीं कराया गया है, कहीं पर नाला बना है तो वह आगे कनेक्ट नहीं है, कहीं पर 20-20 मीटर तक नाला बना ही नही है। नाले में कूड़ा भरा होने के कारण अब नाला एक कूड़ाघर की तरह नजर आने लगा है।

महापौर ने की अपील, नालों में न डालें कूड़ा

महापौर सुनीता दयाल ने शहर के लोगों से अपील की है कि नालों में कूड़ा न डालें, नालों के ऊपर अतिक्रमण भी न करें। जिससे की सफाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो और जलनिकासी हो सके।

उन्होंने अपील की है कि अपने घर और दुकान के सामने नाले की सफाई की जिम्मेदारी शहर के लोग खुद लें। इस बार नाले की सफाई का कार्य समय से और बेहतर तरीके से कराया जा रहा है, यदि लोग भी जागरूक होकर खुद नालों में गंदगी न फेंके जाने की जिम्मेदारी लेंगे तो जलभराव की समस्या नहीं होगी।

नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में दो पक्षों में मारपीट, युवक को लात-घूंसों से पीटते दिखे लोग

दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने वाले का दावा है कि यह वीडियो कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गैलेरिया का है। पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो में एक युवती भी दिखाई दे रही है जो उस युवक को बचाने का प्रयास कर रही है।

नोएडा। मॉल के खुले क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल करने वाले का दावा है कि यह वीडियो कोतवाली सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गैलेरिया का है। पुलिस जांच में जुटी है।

50 सेकंड के इस वीडियो में कुछ लोग पीले रंग की टी-शर्ट पहले युवक की लात-घूंसों से पिटाई कर रहे हैं। बचाव में वह युवक भी हाथापाई करने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच नीले रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट पहने 8-10 लोग आ जाते हैं और पिट रहे युवक को बचाने का प्रयास करते हैं।

ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग मॉल प्रबंधन की ओर से सुरक्षाकर्मी हैं। वह बार-बार पीले रंग की टी-शर्ट पहने युवक को बचाकर सुरक्षित जगह ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीटने वाले लोग बार-बार उसे पकड़ लेते हैं और लात-घूंसे बजाने लगते हैं और जमीन पर घसीटने लगते हैं।

वीडियो में एक युवती भी आई नजर

वीडियो में एक युवती भी दिखाई दे रही है, जो उस युवक को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पीटने वाले युवकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सुरक्षाकर्मी और युवती के प्रयास विफल हो जाते हैं। युवती उन युवकों से मिन्नते करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन आरोपित युवक पीटने से नहीं मान रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष नशे में थे। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, यह अभी साफ नहीं हुआ है। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि वीडियो कहां का और कब का है इसकी जांच कराई जा रही है। दोनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गुड़गांव के भाजपा सांसद को मिली मोदी कैबिनेट में जगह, लगातार 5वीं बार बने मंत्री

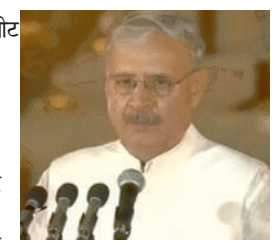

गुरुग्राम। हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की हैट्रिक लगा दी। **लगातार पांचवीं बार बने मंत्री:** राव इंद्रजीत सिंह लगातार पांचवीं बार मंत्री बने हैं। भाजपा सरकार से पहले वह कांग्रेस सरकार में लगातार दो बार मंत्री बने थे। इतने लंबे समय तक लगातार कुछ ही नेता मंत्री रहे हैं। हरियाणा में कोई नेता लगातार पांच बार राव के अलावा संसद भी नहीं पहुंचा है।

लोगों में राव इंद्रजीत की पैठ ही बनी संजीवनी: गुड़गांव लोकसभा सीट पर मतगणना में इस बार काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती दौर में जहां भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों की धड़कने थम गई थीं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर और उनके समर्थक खुशी मनाते दिखे थे। 12 राउंड की गिनती के बाद राव इंद्रजीत सिंह बढ़त बना पाए। उसके बाद राव की लीड को राज बब्बर नहीं तोड़ पाए।

फरीदाबाद एवं पलवल के सभी नागरिकों को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देवेंद्र सिंह

हमारे शहर के सांसद फिर से राज्य मंत्री बने, यह हमारे शहर के लिए एक अच्छी खबर है। अब पुरानी बातों को भूल जाओ नए सिरे से नए-नए कार्य एवं पूरे प्रदेश में एक्शन ग्राउंड पर जल्द शुरू होंगे। एक बार फिर से हमारे शहर फरीदाबाद एवं पलवल के सांसद आदरणीय कृष्णपाल जी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और वह हमारे जिला फरीदाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष भी है हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको राज्य मंत्री बनने पर बहुत-बहुत बधाई और हम सभी चाहेंगे इस बार कुछ हटकर कार्य करे जिससे शहर में एक बड़े लेवल पर बदलाव आए ऐसी हमें पूरी पूरी आशा है खासकर सड़क सुरक्षा पर।

जानिए वैश्विक षड्यंत्रों के बावजूद मोदी का विजय-रथ नहीं रुकने का अर्थ

मनोज ज्वाला

भारतीय जनता पार्टी एवं उसके लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी को येन-केण प्रकारेण सत्ता से बेदखल कर देने के बावत इस बार न केवल देश भर के तमाम विपक्षी दलों ने तमाम प्रकार के हथकण्डों के साथ अब तक की चुनावी राजनीति के इतिहास का सबसे बडा अभियान चलाया।

भारत की 18वीं लोकसभा के चुनाव-परिणाम से पूरी दुनिया विस्मित है, क्योंकि विपक्ष के तमाम अवांछित हथकण्डों-अफवाहों के बावजूद भारतीय राष्ट्रवाद की राजनीति के ध्वजवाहक नरेन्द्र मोदी को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सका और विपक्षी गठबन्धन सत्ता की सुनहरी संडक तक भी नहीं पहुंच पाया। भारतीय जनता पार्टी एवं उसके लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी को येन-केण प्रकारेण सत्ता से बेदखल कर देने के बावत इस बार न केवल देश भर के तमाम विपक्षी दलों ने तमाम प्रकार के हथकण्डों के साथ अब तक (सन 1946 से 2024 तक) की चुनावी राजनीति के इतिहास का सबसे बडा अभियान चलाया, बल्कि देश के बाहर की शक्तियों ने भी बढ-चढ कर उनके उस अभियान को सत्ता की मुकाम तक पहुंचाने की सुनियोजित मुहिम चलायी; लेकिन तब भी भाजपाई राष्ट्रवादी गठबंधन का विजय-रथ पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर सनसनाता हुआ राजपथ पर पहुंच ही गया, जबकि कांग्रेसी सम्प्रदायवादी गिरोह की गाडी किनारे की पगडण्डी पर ही खडी रह गई। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 'राजग' (राष्ट्रीय जनतांत्रिक) नामक गठबंधन को सत्ता के लिए पर्याप्त से भी अधिक लगभग 300 सीटें हासिल हो गईं, तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 'भारावसिग' (भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी) नामक गठबंधन तो नहीं, (क्योंकि सभी कहीं अलग-अलग हैं, तो कहीं एकजुट हैं और कार्यक्रम तो सबके भिन्न-भिन्न हैं) 'गिरोह' कहिए, उसे मात्र 232 सीटें प्राप्त हो सकीं, जो अकेली भाजपा को मिली सीटों से भी कम है। इस गिरोह की यह सामूहिक उपलब्धि तब है, जब उक्त समूह के सभी दलों ने साम्प्रदायिक तुष्टिकरण के आपत्तिजनक व घिनौने खेल का खुला प्रदर्शन किया एवं मतदाताओं को रिश्वत के तौर पर नकदी का प्रलोभन भी दिया और सबसे बडी बात कि उनके पक्ष में बडी-बडी कुख्यात वैश्विक शक्तियों ने भी भाजपा-मोदी विरोधी अभियान चलाया। जी हां वैश्विक रिलीजियस मजहबी शक्तियों ने धर्म (सनातन) व धर्मधारी राष्ट्र (भारत) के पुनरुत्थान से घबरा कर धर्मध्वजवाहक भाजपा-मोदी की राह रोकने के बावत उनके विरुद्ध नकारात्मक जनमत निर्मित करने एवं कृत्रिम असंतोष उत्पन्न करने और वृहतर धार्मिक समाज की राष्ट्रीय एकता को बनावटी जातीय वैमनस्यता से विखण्डित करने का ऐसा अभियान चलाया, जैसा आज तक अन्य किसी देश की सरकार को अपदस्थ करने के लिए नहीं चलाया गया था। तभी तो चुनाव-परिणाम के बाद भारत-सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा-सलाहकार और विभिन्न गोपणीय कार्यक्रमों के सूत्रधार अजित डोभाल को भी कहना पडा कि "इस बार भाजपा की चुनावी लडाई 'कांग्रेस' 'आआपा' 'सपा' व 'ममता' से नहीं थी, अपितु उस 'ग्लोबल पावर' से थी, जो भारत को कमजोर करने के बावत मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने हेतु हिन्दुओं को विभाजित करने का अभियान चला रही थी।"

आपको याद होगा कि ऐन चुनाव के मौके पर ही 'यूएससीआईआरएफ' (यूएस कमिशन फॉर इण्टरनेशनल रिलीजियस फ्रिडम) नामक एक अमेरिकी आयोग और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' नामक अमेरिकी अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि "भारत में भाजपा-मोदी के सत्तासीन रहने से भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है।" अब तो यह खुलासा भी हो चुका है कि 'धर्म (सनातन)-विरोधी' विस्तारवादी रिलीजियस-मजहबी शक्तियों के वैश्विक मुख्यालय- वेटिकन सिटी से संचालित चर्च-मिशनरी संस्थानों तथा उनसे पोषित विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) एवं शैक्षिक-आर्थिक संस्थानों और मीडिया घरानों का एक व्यापक अंतर्जाल इस षड्यंत्रकारी अभियान के क्रियान्वयन में पिछले पांच वर्षों से सक्रिय था (है)। 'हेनरी लुईस फाउण्डेशन', 'जॉर्ज सोरोस ओपेन सोसाइटी फाउण्डेशन' तथा 'बर्कले सेंटर फॉर रिलिजन व पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स' (Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs) एवं 'कार्नेगी इंडॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' (Carnegie Endowment for International Peace) और 'ह्यूमन राइट्स वाच' व 'साउथ एशिया एक्टिविस्ट कलेक्टिव' (एसएएसएसी) ऐसी ही कुछ संस्थायें हैं,

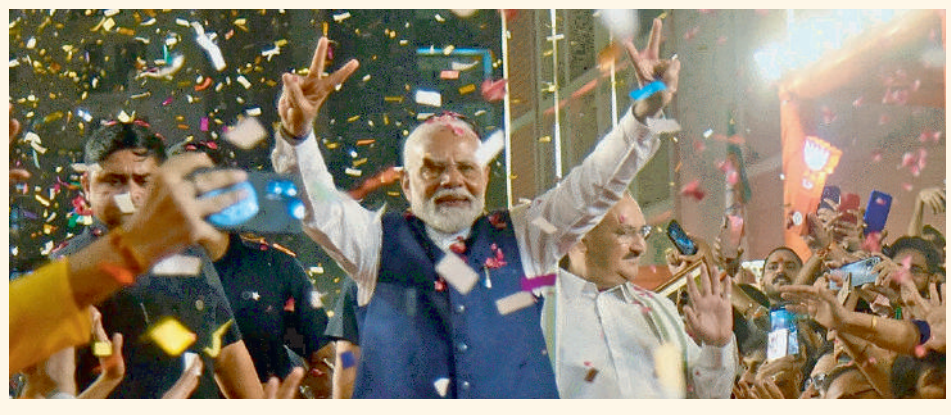

जिन्होंने अपने भारी-भरकम संसाधनों और भारतीय एजेण्टों के सहारे जनमत को नकारात्मक दिशा में रिझाने का काम युद्ध-स्तर पर किया।

'डिसइंफो लैब' नामक एक भारतीय खुफिया एजेन्सी ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य और सत्य का विस्तार से खुलासा किया हुआ है। लैब की रिपोर्ट के अनुसार "भारतीय मतदाताओं को भाजपा-मोदी के विरुद्ध उकसाने-भडकाने के लिए 'हेनरी लुइस फाउंडेशन' और 'जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' ने अपने-अपने विभिन्न कारिन्दों को कडोंरों डॉलर की 'फण्डिंग' करते हुए उनके जरिये भिन्न-भिन्न माध्यमों से खुल कर हस्तक्षेप किया। केवल विदेशी मीडिया के माध्यम से ही नहीं, बल्कि कतिपय भारतीय मीडिया संस्थानों के द्वारा भी फर्जी तथ्यों-मुद्दों-सूचनाओं के आधार पर जनमत निर्मित कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इस बावत किसिम-किसिम के लेखों, शोध-पत्रों और आंकडों के माध्यम से आम-चुनाव को प्रभावित करने सम्बन्धी टिप्पणियां प्रकाशित-प्रसारित कीं गईं।" डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में 'हेनरी लुइस फाउंडेशन' (एचएलएफ) और 'जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन' (ओएसएफ) के अतिरिक्त जिन समूहों और व्यक्तियों का नाम उजागर किया गया है, उनमें कनाडा के रिकन पटेल की संस्था- 'नामती' और फ्रांस के एक राजनीतिक विश्लेषक- क्रिस्टोफ जॉफरलॉट प्रमुख हैं। लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय मतदाताओं के रुझान की दिशा बदलने के लिए 'एचएलएफ ने 'नामती' को तीन लाख डॉलर और 'ओएसएफ' ने 13.85 करोड़ डॉलर से वित्त-पोषण किया। डिसइंफो लैब ने यह भी दावा किया है कि "चुनाव के दौरान भाजपा-मोदी को क्षति पहुंचाने वाला वातावरण निर्मित करने के बावत 'एचएलएफ' द्वारा कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों और पाकिस्तान की 'आईएसआई' को भी आर्थिक सहयोग दिया गया था।" लैब ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि "क्रिस्टोफ और उसके सहयोगी-साथी गाइल्स वर्नियर्स ने भारत के सोनीपत-स्थित अशोक विश्वविद्यालय में 'त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा' (टीसीपीडी) के माध्यम से भाजपा-मोदी-विरोध पर आधारित जातीय वैमान्यस्यता की एक फर्जी कहानी को जबरन बढ़ावा दिया और उसके द्वारा शोसल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह प्रचारित किया कि भारतीय राजनीति में निचली जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।" रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि क्रिस्टोफर ने वर्ष 2021 में ही 'भारत में जातीय जनगणना की आवश्यकता' पर एक सामग्री तैयार की थी, जिसे भारत में चुनावी मुद्दा बनवाने हेतु उसे अमेरिकी 'हेनरी लुइस फाउंडेशन' (एचएलएफ) ने अत्यधिक धनराशि दी थी।

इतना ही नहीं, डिसइंफो लैब की मानें तो 'एचएलएफ' द्वारा जाफरलॉट को 'हिंदू बहुसंख्यकों के समय में मुस्लिम' (Muslims in a Time of Hindu Majoritarianism) शीर्षक लेख-परियोजना पर काम करने के लिए भी 3.85 लाख डॉलर की धनराशि दी गई थी। डिसइंफो लैब ने दावा किया है कि एचएलएफ ने वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 तक भाजपा-मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए 'बर्कले सेंटर फॉर रिलिजन, पीस एंड वर्ल्ड अफेयर्स' (Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs) को भी 3.46 डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसके बदले बर्कले संस्थान ने 'हिंदू अधिकार और भारत की धार्मिक कूटनीति (The Hindu Right and India's Religious Diplomacy) पर सामग्री तैयार की थी। इसी तरह से एचएलएफ ने 'सीईआईपी' यानी 'कार्नेगी इडॉमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस' (Carnegie Endowment for International Peace) को 'सत्तावादी दमन, हिंदू राष्ट्रवाद (Authoritarian repression, Hindu Nationalism) नामक भाजपा-मोदी-हिन्दुत्व-विरोधी बौद्धिक परियोजना-सामग्री तैयार करने के लिए 1.20 लाख डॉलर की धनराशि दी थी। डिसइंफो के अनुसार 'सीईआईपी' को वर्ष 2019 में ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 'सत्ता में भाजपाः भारतीय लोकतंत्र और धार्मिक राष्ट्रवाद' (The BJP in Power: Indian Democracy and Religious Nationalism) नामक परियोजना-सामग्री तैयार करने के लिए भी 40 हजार डॉलर की धनराशि दी गई थी। डिसइंफों की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एचएलएफ ने 'साउथ एशिया एक्टिविस्ट कलेक्टिव' (एसएएसएसी) नामक मिशनरी को भी 'हिंदू राष्ट्रवाद' नामक भाजपा-मोदी विरोधी सामग्री तैयार करने के लिए बड़ी धनराशि दी थी। यह तो कुछ उदाहरण मात्र हैं, जबकि पूरा मामला यह है कि भारत में चुनावी हवा का रुख बदल डालने के लिए चीन अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस कनाडा की अनेक चर्च-मिशनरी संस्थाओं ने भारतीय मीडिया संस्थानों व शोसल मीडिया प्लेटफार्मों एवं कतिपय शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रभावी बौद्धिक-वैचारिक स्रोतों को एक प्रकार से खरीद कर भाजपा-मोदी रोको अभियान में लगा रखा था।

जाहिर है, ऐसे भीषण वैश्विक विखण्डनकारी रिलीजियस-मजहबी षड्यंत्रों के बावजूद थोड़े झटकों-हिचकोलों के साथ भाजपा-राजग का विजय-रथ विरोधियों को पछाड़ते हुए सीधे राजपथ पर पहुंच गया और नरेंद्र मोदी पुनः सत्तासीन हो गए, तो इसके अनेक अर्थ हैं, जिनमें से एक यह भी है कि धर्मधारी भारत का पुनरुत्थान एक दैवीय अभियान है, जो पूर्णता को प्राप्त हुए बिना अब कतई नहीं रुकेगा, किन्तु वृहतर धार्मिक समाज को इससे दृढ़तापूर्वक जुड़े रहना होगा।

जून 2024 में ब्रिटिश कार कंपनी दे रही लाखों रुपये बचाने का मौका, जानें किस पर है क्या ऑफर

ब्रिटिश वाहन निर्माता एमजी मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से June 2024 के दौरान कई कारों पर लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी किस गाड़ी पर इस महीने में कितना डिस्काउंट ऑफर कर रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। June 2024 में अगर आप कार, एसयूवी या EV खरीदने का मन बना रहे हैं, तो MG Motors अपनी कारों पर हजारों रुपये के डिस्काउंट ऑफर दे रही है। कंपनी की ओर से किस कार पर कितना डिस्काउंट कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

MG Gloster

एमजी की ओर से फुल साइज एसयूवी के तौर पर Gloster को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस महीने में इस एसयूवी पर अधिकतम 3.10 लाख रुपये के ऑफर दे रही है। यह ऑफर इसके 2023 मॉडल्स पर दिए जा रहे हैं। जिनमें स्पेशल डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस, एक्सचेंज डिस्काउंट और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हैं। कंपनी की ओर से 2024 वाले मॉडल्स पर भी 2.35 लाख रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं।

MG ZS EV

एमजी की ओर से इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर ZS EV को लाया जाता है। June 2024 में इस एसयूवी पर भी लाखों रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। कंपनी इस महीने में इस एसयूवी के एक्सक्लूजिव प्लस और एसेंस वेरिएंट्स पर 1.85 लाख रुपये के ऑफर दे रही है। इसमें लॉयल्टी बोनस, एक्सचेंज डिस्काउंट और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हैं। अगर आप 2023 में बनी हुई जेडएस ईवी को खरीदते हैं तो आपको 2.35 लाख रुपये तक बचाने का मौका मिल सकता है।

MG Hector

कंपनी की ओर से Hector एसयूवी को भी बेहतरीन फीचर्स के साथ ऑफर किया जाता है। लेकिन इस महीने इस एसयूवी पर 85 हजार रुपये से लेकर 1.85 लाख रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी इस एसयूवी पर स्पेशल डिस्काउंट, लॉयल्टी बोनस, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट के तौर पर यह ऑफर दे रही है। कंपनी 2023 में बनीं यूनिट्स पर भी इस महीने में 2.15 लाख रुपये तक के ऑफर दे रही है।

MG Astor

कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Astor को भी June 2024 में खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। कंपनी इस महीने में इस एसयूवी के 2024 मॉडल्स पर 75 हजार रुपये से लेकर 1.35 लाख रुपये तक के ऑफर दे रही है। इसके अलावा इसके 2023 के बने मॉडल्स पर भी इस महीने में अधिकतम 2.30 लाख रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

MG Comet

कंपनी की ओर से देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर Comet को ऑफर किया जाता है। इस कार पर इस महीने में सिर्फ 40 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

Vinfast VF e34 को टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट, लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स के साथ जल्द होगी लॉन्च

Vinfast VF e34 वर्तमान में वियतनाम और इंडोनेशिया में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह ऑटोमेकर की अपनी रेंज में सबसे छोटी गाड़ी है। इसमें 110kW का बैटरी पैक लगा है जिसकी दावा की गई रेंज 318km है। आगामी गाड़ी को हाल ही में परीक्षण के दौरान देखा गया है। जिससे संकेत मिलता है कि यह जल्द ही भारत में आएगी।

नई दिल्ली। वियतनाम की विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में नए प्लांट की शुरुआत की थी। अब इसके कुछ समय बाद ही कंपनी ने अपनी गाड़ियों का भारत में परीक्षण करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कंपनी के नेक्स्ट लाइनअप में शामिल Vinfast VF e34 को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। परीक्षण के दौरान मिड-साइज SUV के बारे में कई जानकारी मिली है।

पावरट्रेन और आकार

VF e34 वर्तमान में वियतनाम और इंडोनेशिया में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह ऑटोमेकर की रेंज में सबसे छोटी गाड़ी है। इसमें 110kW का बैटरी पैक लगा है जिसकी दावा की गई रेंज 318km है और टॉप स्पीड का समय 9 सेकेंड में 0 से100kmph तक पहुंचने का है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 4.3-मीटर लंबा है और इसका व्हीलबेस 2.6-मीटर है जो इसे किआ सेल्टोस/हुंडई क्रेटा/मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइडर/होंडा एलिवेट और MG एस्टोर के समान आकार की रेंज में रखता है।

केबिन और फीचर लिस्ट

टेस्टिंग से पता चलता है कि केबिन पूरी तरह से ग्रे रंग का है जिसमें क्रोम इन्सर्ट और डुअल-डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें से एक वर्टिकल यूनिट है और उसका आकार बड़ा है। फीचर्स की बात करें तो लेवल-2 ADAS, क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल USB चार्जिंग पोर्ट, हाईलाइन TPMS, कनेक्टेड कार तकनीक और 360-डिग्री कैमरा देखने को मिल सकता है।

कीमत और मुकाबला

यह पहली बार है जब हमने भारत में e34 को देखा है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह Vinfast के लाइनअप के हिस्से के रूप में यहाँ आएगी। उम्मीद है कि इसकी कीमत 20 लाख से 25 लाख रुपये के बीच होगी और यह MG ZS EV, मारुति eVX, किआ कैरेंस EV और महिंद्रा XUV.e8, होंडा एलिवेट EV और टोयोटा अर्बन स्पोर्ट कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन से मुकाबला करेगी। फिलहाल भारत में इसके लॉन्च को लेकर ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है।

मारुति की प्रीमियम कारों पर जून 2024 में मिल रहा हजारों रुपये डिस्काउंट, जानें किस पर क या है ऑफर

देश में सबसे ज यादा कारों की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से June 2024 में Nexa डीलरशिप पर उपलब्ध कारों और एसयूवी पर हजारों रुपये के डिस-काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से किस कार को खरीदने पर कितना कैश डिस-काउंट एक सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस के तौर पर डिस-काउंट ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। June 2024 में अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी Nexa की कई कारों पर कंपनी की ओर से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से किस कार पर कितना डिस्काउंट कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Maruti Grand Vitara

देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता की ओर से अपनी प्रीमियम एसयूवी Grand Vitara पर June 2024 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को इस महीने खरीदने पर 74 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस एसयूवी पर इस महीने में 74 हजार रुपये तक के ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।

Maruti Baleno

June 2024 में मारुति बलेनो पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से इस महीने में हैचबैक को खरीदने पर 57 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। मारुति बलेनो की एक्स शोरूम कीमत 6.66 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Maruti Jimny

मारुति की ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर आने वाली जिम्नी पर भी June महीने में 50 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं। कंपनी की इस एसयूवी को 12.74 लाख रुपये की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Maruti Ciaz

मारुति की मिड साइज सेडान कार सियाज की एक्स शोरूम कीमत 9.40 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कार को June 2024 में खरीदने पर अधिकतम 45 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

Maruti Xl6

कंपनी की लग्जरी एमपीवी के तौर पर आने वाली Xl6 पर June 2024 में 20 हजार रुपये की छूट मिल रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11.61 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Maruti Fronx

मारुति की एक और एसयूवी Fronx को June 2024 में खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस एसयूवी पर कंपनी इस महीने में 27 हजार रुपये के ऑफर्स दे रही है। इसकी कीमत 7.51 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

बीते चार सालों में यात्री वाहनों के निर्यात में हुई 2.68 लाख यूनिट की बढ़ोतरी, जानें किस कंपनी ने किया सबसे ज्यादा निर्यात

भारत में बनीं कारों की दुनिया के कई देशों में मांग रहती है। देश में कई प्रमुख कंपनियों की ओर से वाहनों का निर्यात भी किया जाता है। बीते चार साल में कारों के निर्यात में कैसा प्रदर्शन रहा है। किस कंपनी की ओर से कितनी कारों का निर्यात किया गया है। सबसे ज यादा हिस-सेदारी किस कंपनी की रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। दुनियाभर में कारों की मांग में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी कारों की बिक्री हर महीने काफी बेहतर रहती है। इसके साथ ही भारत में बनीं कारों को दुनिया के कई देशों में निर्यात भी किया जाता है। बीते चार सालों में मेड इन इंडिया कारों का निर्यात कैसा रहा है। किस कंपनी की किती हिस्सेदारी रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितना हुआ निर्यात

भारत से हर महीने बड़ी संख्या में यात्री वाहनों का निर्यात दुनिया के कई देशों में होता है। जानकारी के मुताबिक बीते चार सालों में भारत से यात्री वाहनों के निर्यात में 2.68 लाख यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 वित्तीय वर्ष में यात्री वाहनों का निर्यात 4,04,397 यूनिट रहा। यह 2021-22 वित्तीय वर्ष में बढ़कर 5,77,875 यूनिट और 2022-23 वित्तीय वर्ष में 6,62,703 यूनिट हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में निर्यात 6,72,105 यूनिट रहा, जो 2020-21 से 2,67,708 यूनिट ज्यादा है। SIAM के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में कुल PV निर्यात 6,72,105 यूनिट रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में 6,62,703 यूनिट से 1.4 प्रतिशत ज्यादा है।

सबसे ज यादा किसने किया निर्यात

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में, मारुति सुजुकी ने उद्योग भर में 2,67,708 यूनिट की बढ़ोतरी में से 70 फीसदी का योगदान दिया है, जिन्हें विदेशी बाजारों में भेजा गया था। ऑटो प्रमुख के निर्यात शिपमेंट में वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 24 के बीच 1,85,774 यूनिट की बढ़ोतरी हुई।

कई कारकों से मिली मदद

मारुति सुजुकी इंडिया के कॉर्पोरेट मामलों के कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने कहा कि ज्यादा मॉडलों को जोड़ने, वैश्विक उत्पादन मानकों का पालन करने और टोयोटा के साथ गठजोड़ जैसे कारकों ने निर्यात की मात्रा को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि कंपनी वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 100 देशों में मॉडल निर्यात कर रही है।

किन देशों में है मांग

मारुति के लिए टॉप विदेशी बाजारों में दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चिली और मैक्सिको हैं। इनके अलवा कंपनी के प्रमुख बाजारों में फिलीपींस, इंडोनेशिया और आइवरी कोस्ट भी शामिल हैं।

किन कारों की रही मांग

मारुति की बलेनो, डिजायर, स्विफ्ट, एस-प्रेसो, ग्रैंड विटारा, जिम्नी, सेलेरियो और एर्टिगा जैसे मॉडल्स की दुनियाभर में काफी मांग रहती है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 2,80,712 यूनिट्स का निर्यात किया, जो वित्त वर्ष 2023 में 2,55,439 यूनिट्स से 10 प्रतिशत अधिक है।

दूसरे पायदान पर रही हुंडई

मारुति के अलावा हुंडई ने भी निर्यात के मामले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 1,63,155 यूनिट्स का निर्यात किया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में 1,53,019 यूनिट्स का ही निर्यात किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक हुंडई ने निर्यात के मामले में सात फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है।

जब चुनाव सर्वेक्षण गलत साबित हो जाए

हरि जयसिंह

यह विस्तृत शृंखला दर्शाती है कि हमारे जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में सीटों की संख्या का अनुमान लगाना कितना मुश्किल है। इसके अलावा, सीटों की संख्या पर ध्यान अक्सर मतदाता के व्यवहार और भविष्यवाणियों के पीछे के कारणों की गहरी अंतर्दृष्टि पर हावी हो जाता है।

भारत के आम चुनाव में कई हफ्तों के गहन प्रचार के बाद मतदान 1 जून को समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद मीडिया कई सर्वेक्षणकत्र्ताओं के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए दौड़ पड़ा। सभी सर्वेक्षणों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बड़ी जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का संकेत दिया। सर्वेक्षणों के अनुसार, साजिश यह थी कि भाजपा की जीत कितनी महत्वपूर्ण होगी, 543 सीटों वाली संसद में 281 से 401 सीटों तक की भविष्यवाणी की गई थी।

यह विस्तृत शृंखला दर्शाती है कि हमारे जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में सीटों की संख्या का अनुमान लगाना कितना मुश्किल है। इसके अलावा, सीटों की संख्या पर ध्यान अक्सर मतदाता के व्यवहार और भविष्यवाणियों के पीछे के कारणों की गहरी अंतर्दृष्टि पर हावी हो जाता है। 2024 दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष होने के कारण चुनावों को गहन जांच का सामना करना पड़ता है। ऐसे युग में जहां डाटा सार्वजनिक भावना को मापने और चुनावी परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि सबसे परिष्कृत एल्गोरिदम और पद्धतियां भी कभी-कभी अप्रत्याशित गलत अनुमान लगा सकती हैं जो विश्लेषकों और जनता को समान रूप से चकित कर देती हैं।

उदाहरण के लिए 2016 और 2020 में अमरीकी चुनाव और 2016 के ब्रैग्जिट जनमत संग्रह ने चुनावों की विश्वसनीयता और प्रभाव के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। आइए हम हाल के इतिहास के कुछ उल्लेखनीय सर्वेक्षणों पर नजर डालें जहां सर्वेक्षणकत्र्ताओं ने इसे गलत पाया और इन चूकों के पीछे के कारण बताए।

2016 अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव : अधिकांश प्रमुख सर्वेक्षणों ने डोनाल्ड ट्रम्प पर हिलेरी क्लिंटन की जीत की भविष्यवाणी की। हकीकत तो यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए थे। सर्वेक्षणों में स्विंग राज्यों में ट्रम्प के समर्थन को कम करके आंका गया और उन जनसांख्यिकीय समूहों को ध्यान में रखने में विफल रहे जो ट्रम्प के लिए उम्मीद से अधिक बड़ी संख्या में आए थे।

2016 ब्रैग्जिट जनमत संग्रह : सर्वेक्षणों से पता चला कि 'बचा हुआ' खेमा जीतेगा। हालांकि 'छोड़ें' पक्ष को 52 प्रतिशत वोट मिले। सर्वेक्षणकत्र्ता वृद्ध मतदाताओं और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में 'छोडने' के लिए अधिक इच्छुक लोगों के बीच भारी मतदान से चूक गए थे।

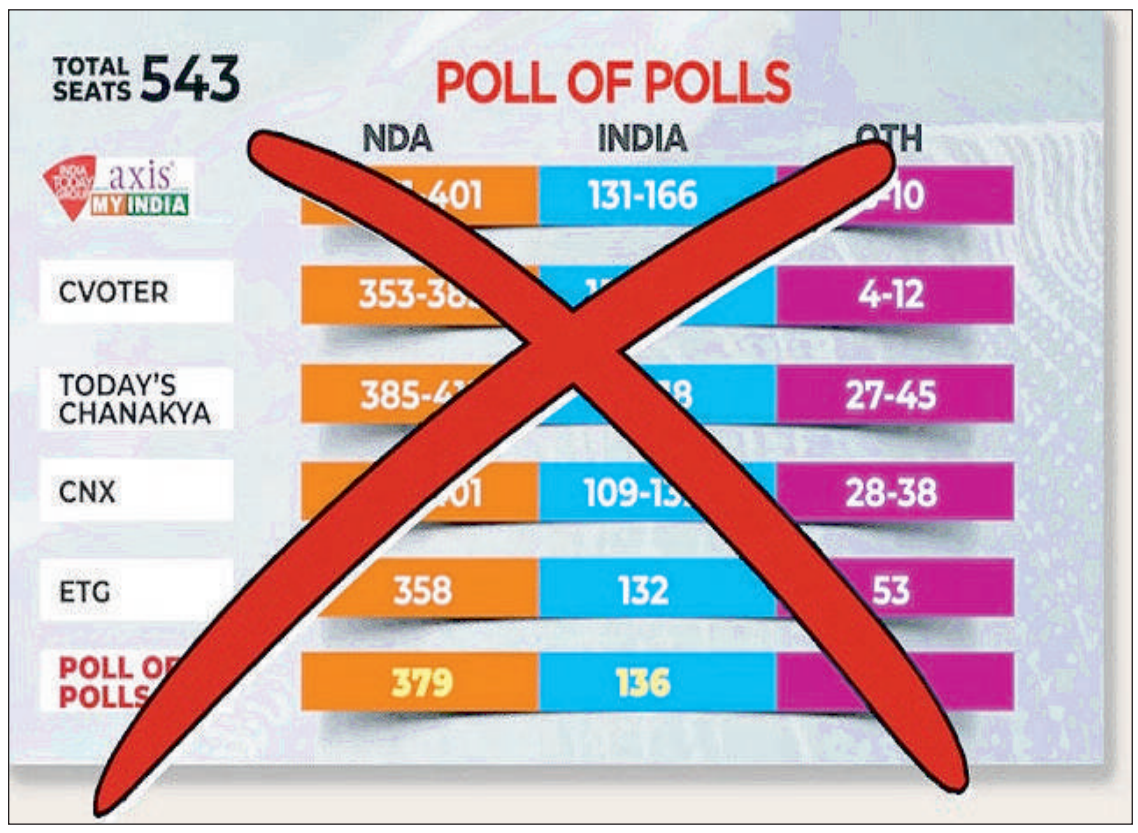

2015 यू.के. आम चुनाव : सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया गया, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दों और 'शर्मीले टोरी' मतदाताओं को कम आंकने के कारण यह गलत आंकलन हुआ।

2019 ऑस्ट्रेलियाई संघीय चुनाव : सर्वेक्षणों ने लिबरल-नैशनल गठबंधन पर ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी की जीत की भविष्यवाणी की। हालांकि, लिबरल-नैशनल गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। चुनाव, विशेष रूप से क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मतदाताओं के समर्थन को सटीक रूप से हासिल करने में विफल रहे।

2019 इसराईली चुनाव : सर्वेक्षणों ने संकेत दिया कि ब्लू एंड व्हाइट पार्टी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी पर जीत हासिल करेगी। दरअसल, लिकुड और उसके सहयोगियों ने एक गठबंधन बनाया, जिससे नेतन्याहू सत्ता में बने रह सके। सर्वेक्षणकत्र्ताओं ने नेतन्याहू के आधार के बीच मतदान प्रतिशत और उनके अंतिम समय के प्रचार अभियान के प्रभाव को कम करके आंका। ये उदाहरण मतदान की जटिलताओं और अंतर्निहित अनिश्चितताओं को उजागर करते हैं। वे मानव व्यवहार की अप्रत्याशित प्रकृति को बेहतर ढंग से पकडने के लिए मतदान पद्धतियों में निरंतर सुधार की आवश्यकता की याद दिलाते हैं।

भारत में, पिछले अढ़ाई दशकों में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से विकास के साथ एग्जिट पोल व्यापक हो गए हैं। हालांकि, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए, मतदान समाप्त होने तक एग्जिट पोल के परिणामों को आयोजित करने और प्रसारित करने पर रोक लगाती है। इसलिए कोई यह पूछ सकता है कि क्या वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? यह देखते हुए कि आधिकारिक चुनाव परिणाम कुछ ही दिनों में घोषित किए जाते हैं? वे क्या मूल्य प्रदान करते हैं? इस बात पर चर्चा हुई है कि क्या उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए।

यद्यपि अक्सर अशुद्धियों के लिए आलोचना की जाती है लेकिन मतदाता व्यवहार में डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करके, अनुमान के स्थान पर सूचित विश्लेषण की पेशकश करके सर्वेक्षण लोकतांत्रिक समाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2004 में वाजपेयी की वापसी की भविष्यवाणी, ब्रैग्जिट के 'शेष' वोट और हिलेरी क्लिंटन की जीत जैसी त्रुटियों के बावजूद अच्छे सर्वेक्षण आम तौर पर नुकसान की तुलना में अधिक अच्छा करते हैं।

एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य जैसे भारतीय सर्वेक्षणकत्र्ताओं ने अपने अनुमानों में सराहनीय सटीकता दिखाई है जिससे अक्सर विजेता सही साबित होता है। फिर भी कार्यप्रणाली संबंधी खामियों और मीडिया की संपूर्ण खुलासों को रोकने की प्रवृत्ति के कारण जनता में अविश्वास बना रहता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मतदान डाटा का भ्रामक चित्रण होता है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिए, मीडिया पर पूर्ण खुलासे और त्रुटि की संभावनाओं सहित स्थिति की वास्तविकता को ईमानदारी से प्रस्तुत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग आवश्यक है कि चुनाव भ्रम के स्रोत के बजाय एक मूल्यवान उपकरण के रूप में काम करें।

संपादक की कलम से

'अब रिश्वत अदा कीजिए'' चंद किस्तों में'

देश में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी हैं कि आम जनता के लिए चंद सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दिए बिना काम करवाना मुश्किल हो गया है जिनमें पुलिस विभाग भी शामिल है। गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद 'राम भाई मोकरिया' ने 30 मई, 2024 को स्वीकार...

देश में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी हैं कि आम जनता के लिए चंद सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दिए बिना काम करवाना मुश्किल हो गया है जिनमें पुलिस विभाग भी शामिल है। गुजरात से भाजपा के राज्यसभा सांसद 'राम भाई मोकरिया' ने 30 मई, 2024 को स्वीकार किया कि ''राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और कोई भी अधिकारी तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी जेब गर्म न की जाए। मुझे भी 'फायर एन.ओ.सी.' के लिए 70,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ी थी।'' यह केवल गुजरात की ही नहीं पूरे देश की कहानी है। पहले तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नकद रकम अथवा वस्तुओं आदि के रूप में ही रिश्वत लिया करते थे, परंतु अब उन्होंने 'यू.पी.आई.' और 'गूगल पे' जैसे धन हस्तांतरण के माध्यमों के साथ-साथ किस्तों ('ई.एम.आई.') द्वारा भी रिश्वत लेनी शुरू कर दी है।

* 20 मई को लुधियाना में विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने नगर निगम जोन-ए में तैनात एक क्लर्क को 'गूगल पे' के जरिए 2500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

* 28 मई को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने बदायूं के थाना इस्लाम नगर की इंस्पैक्टर सिमरनजीत कौर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

* 5 जून को विजीलैंस विभाग ने नगर कौंसिल मानसा में तैनात जे.ई. जतिंदर सिंह को एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

* 6 जून को विजीलैंस ब्यूरो ने थाना घड़ुआं, एस.ए.एस. नगर में तैनात हवलदार मनप्रीत सिंह को 2500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।

इन दिनों लोगों के मकान, वाहन अथवा कोई अन्य महंगी वस्तु एकमुश्त अदायगी करके खरीदने में असमर्थ होने पर विभिन्न कंपनियों द्वारा उसकी कीमत किस्तों ('ईक्वेटेड मंथली इंस्टालमैंट' यानी 'ई.एम.आई.') में अदा करके महंगा सामान खरीदने की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी तर्ज पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने रिश्वत देने वालों पर एक ही बार रिश्वत की रकम देने का अधिक बोझ न पड़े इसलिए अब 'ईक्वेटेड मंथली इंस्टालमैंट' ('ई.एम.आई.') द्वारा रिश्वत लेनी शुरू कर दी है जैसे कि वे रिश्वत देने वाले पर एहसान कर रहे हों।गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक व डी.जी.पी. (कानून व्यवस्था) शमशेर सिंह के अनुसार इस वर्ष किस्तों में रिश्वत के लेन-देन के कई मामले सामने आए हैं और यह तरीका काफी लोकप्रिय हो रहा है।

*इसी वर्ष मार्च में स्टेट जी.एस.टी. फर्जी बिलिंग घोटाले में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। इस रकम को 2-2 लाख रुपए की 10 और एक लाख रुपए की एक 'ई.एम.आई.' में बांटा गया ताकि रिश्वत देने वालों को कठिनाई न हो।

* 4 अप्रैल को सूरत में एक डिप्टी सरपंच और तालुका पंचायत सदस्य ने गांव के ही एक व्यक्ति से किसी काम के एवज में 85,000 रुपयों की रिश्वत मांगी, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आरोपियों ने उस पर 'दया' करके उसे 'ई.एम.आई.' का विकल्प दिया, जिसके अंतर्गत उसे 35,000 रुपए पहले और बाकी रकम तीन किस्तों में अदा करने की 'सुविधा' प्रदान की गई।

* गुजरात के साबरकांठा में भी 2 भ्रष्टों पुलिस कर्मियों ने एक व्यक्ति से तयशुदा 10 लाख रुपए रिश्वत में से 4 लाख रुपए की रिश्वत की पहली किस्त ली और चंपत हो गए।

* एक अन्य मामले में एक साइबर क्राइम पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी। उसने इन 10 लाख रुपयों को अढ़ाई-अढ़ाई लाख रुपयों की चार किस्तों में बांट दिया।

चिंतन

ब्रैस्ट कैंसर : मौत के मुहाने पर लाखों शहरी महिलाएं

द लैंसेट कमीशन के विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि स्तन कैंसर से 2040 तक हर साल दस लाख लोगों की मौत होने की आशंका है। अभी भी हर साल 6-7 लाख महिलाओं की इस कैंसर के कारण जान जा रही है, इन आंकड़ों के और भी बढऩे का खतरा है।

द लैंसेट कमीशन के विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि स्तन कैंसर से 2040 तक हर साल दस लाख लोगों की मौत होने की आशंका है। अभी भी हर साल 6-7 लाख महिलाओं की इस कैंसर के कारण जान जा रही है, इन आंकड़ों के और भी बढऩे का खतरा है। हालिया अध्ययनों में ङ्क्षचता जताई गई है कि महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर जिस गति से बढ़ता जा रहा है ऐसे में आशंका है कि साल 2040 तक इसके मामले और मृत्यु का खतरा कई गुना और अधिक हो सकता है। ग्रामीण महिलाओं की बजाय शहरी महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा 10 गुना ज्यादा है।

भारत में महिला-पुरुष दोनों में कैंसर और इसके कारण होने वाली मौतों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्तन कैंसर अब दुनिया नहीं बल्कि भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अस्पतालों में आ रहे मरीजों की लंबी कतारें इसकी गवाह हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े महिलाओं की तरफ ब्रैस्ट कैंसर के बहाने बढ़ती मौत की कहानी बता रही हैं। लैंसेट कमीशन की हालिया जारी रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 के अंत तक 5 वर्षों में लगभग 7.8 मिलियन (78 लाख से अधिक) महिलाओं में स्तन कैंसर का निदान किया गया और लगभग 6.85 लाख महिलाओं की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। आयोग का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के मामले 2020 में 23 लाख से बढ़कर साल 2040 तक 30 लाख से अधिक हो सकते हैं।

अमरीका के एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैडीसिन में प्रोफैसर और शोधकत्र्ता रेशमा जागसी कहती हैं, महिलाओं को इस बढ़ती स्वास्थ्य समस्या को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी बहुत आवश्यक है, जिससे समय पर इसके जोखिमों की पहचान करने में मदद मिल सके। रिसर्च का मानना है 2040 तक इस बीमारी से होने वाली मौतों का जोखिम प्रति वर्ष दस लाख से अधिक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया, भारतीय महिलाओं में भी स्तन कैंसर का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ब्रैस्ट कैंसर का सबसे बड़ा खतरा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में देखा जा रहा है, जहां महिलाएं असाधारण रूप से इससे प्रभावित हो रही हैं।

स्मोकिंग, शराब का चलन बड़ा कारण: विशेषज्ञों के अनुसार ब्रैस्ट कैंसर के शहरी महिलाओं में तेजी से बढऩे का बड़ा कारण धूम्रपान और मद्यपान है। शहरों में पुरुषों के साथ महिलाओं में भी धूम्रपान करना और शराब पीना एक संस्कृति बन चुका है। महिलाएं इसे स्टेटस सिंबल का नाम देती हैं। वो नहीं जानतीं कि उनकी ये च्वाइस उनके शरीर से खिलवाड़ है। अध्ययनों में पाया गया है कि शराब और धूम्रपान के कारण भी स्तन कैंसर का खतरा हो सकता है, इन आदतों से दूरी बनाकर भी स्तन कैंसर के जोखिमों को कम किया जा सकता है। बिगड़ता लाइफस्टाइल, बढ़ता हुआ वजन और ओवरवेट महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर का बड़ा खतरा है।

दोबारा ब्रैस्ट कैंसर होना बड़ा खतरा, ज्यादा घातक : 50 से कम उम्र की महिलाओं में 86 प्रतिशत तक दोबारा ब्रैस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल कैंब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में ये आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि 50 साल से कम उम्र की जिन महिलाओं में एक बार ब्रैस्ट कैंसर का इलाज हो चुका है उनमें दूसरी बार कैंसर होने का खतरा 86 प्रतिशत बढ़ जाता है। जो महिलाएं पहले ब्रैस्ट कैंसर का इलाज करा चुकी हैं वह इसके रिपीट होने की शिकार कभी भी हो सकती हैं। वहीं, दूसरी जगह पहले इसका इलाज करा चुकी 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर होने की आशंका 17 प्रतिशत से ज्यादा है।

क्या महिलाएं ब्रैस्ट कैंसर पर काबू पा सकती हैं : ब्रैस्ट कैंसर पर काबू पा लिया जाए ऐसा अभी संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि सावधानी बरत कर और सजग रहते हुए ब्रैस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। इसके खतरे को कम किया जा सकता है। ब्रैस्ट कैंसर को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और रिसर्च एजैंसियों दोनों की स्पष्ट सलाह है कि कम उम्र से ही महिलाओं, बच्चियों को ब्रैस्ट कैंसर के प्रति जागरुक किया जाए। उन्हें ब्रैस्ट कैंसर को लेकर शुरूआत से ही सावधानी बरतने की सलाह दी जाए, तो इसके खतरे कई गुना कम हो सकते हैं।

कैंसर विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि महिलाओं द्वारा स्तन की नियमित रूप से जांच कराने, अपने जोखिम कारकों की पहचान और बचाव के लिए उपाय करते रहना इस कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल जिस प्रकार के

वैश्विक रुझान देखे जा रहे हैं ऐसे में आशंका है कि इस कैंसर के मामले स्वास्थ्य विभाग पर बड़े दबाव का कारण बन सकते हैं। ब्रैस्ट कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जागरुकता अभियानों की बहुत जरूरत है। ये अभियान समय-समय पर नहीं बल्कि रैगुलर बेसिस पर चलने चाहिएं। स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, पब्लिक प्लेस पर इसकी बात होनी चाहिए। समय-समय पर कैंसर की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि समस्या का समय रहते निदान किया जा सके।

-सीमा अग्रवाल

गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता में फिर प्रवेश कर रहा भारत

मुझे लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार करने में कुछ समय लगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पिछले दशक में केंद्र और कई राज्यों में कम से कम एक दर्जन चुनावों की देखरेख की है।

मुझे लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार करने में कुछ समय लगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पिछले दशक में केंद्र और कई राज्यों में कम से कम एक दर्जन चुनावों की देखरेख की है। मैं भी कई अन्य लोगों की तरह परिणामों से चकित था। लेकिन जैसे-जैसे प्रचार और उन्माद शांत होता जा रहा था जनादेश के विभिन्न पहलू स्पष्ट रूप से सामने आ रहे थे। भाजपा समर्थकों के लिए यह राहत और आश्वासन की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में लौट रही है। हालांकि संख्यात्मक रूप से कम होने के बावजूद भाजपा किसी भी अन्य व्यवस्था की तुलना में स्थिर सरकार प्रदान करने में सक्षम एकमात्र पार्टी बनकर उभरी।

पूर्व और दक्षिण में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केरल में पार्टी ने अपनी पहली संसदीय सीट जीती और उसका वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2024 में 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया।तेलंगाना में इसकी सीटें दोगुनी हो गईं, जबकि वोट शेयर 19 प्रतिशत से बढ़कर प्रभावशाली 35 प्रतिशत हो गया। तमिलनाडु में हालांकि पार्टी कोई भी सीट जीतने में विफल रही लेकिन उसका वोट शेयर 3 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत हो गया। पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ओडिशा विधानसभा चुनाव में जीत और राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सत्तारूढ़ दल को सबसे बड़ा झटका और शर्मदगी उत्तर प्रदेश से मिली, एक ऐसा राज्य जहां से उसे बहुत उम्मीदें थीं। उस स्थिति में परिणाम गंभीर आत्मनिरीक्षण की मांग करते हैं। केंद्र और राज्य में लोकप्रिय सरकारों और अयोध्या और काशी में इतने अच्छे काम और बदलाव के बावजूद, भाजपा अपनी लगभग आधी सीटें हार गई। हालांकि गंभीर आत्ममंथन आवश्यक है, लेकिन अपमानजनक अपमान अनावश्यक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में भी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। बंगाल की राजनीति में वाम मोर्चे की 6 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर वापसी भी एक वजह हो सकती है। हालांकि इन और अन्य राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अधिक जटिल कारण प्रतीत होते हैं।

बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि 'इंडिया' गठबंधन इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन अंत में घटक दलों, विशेष रूप से कई राज्यों में कांग्रेस, और सपा, टी.एम.सी., द्रमुक, राकांपा-एस.पी., शिवसेना-यू.बी.टी. और अन्य ने अपने-

अपने राज्यों में सराहनीय लाभ कमाया, जिससे गठबंधन की संख्या 230 से ऊपर हो गई। देश की लगभग आधी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ाने में सफल रही। देश के नजरिए से इन नतीजों का मिला-जुला संदेश है। चुनाव प्रचार के दौरान एक समाचार चैनल से बात करते हुए पी.एम. मोदी ने कहा कि वह '2014 से 2024 तक एक मजबूत विपक्ष' से चूक गए। उन्होंने टिप्पणी की, 'अगर मेरे जीवन में किसी चीज की कमी है, तो वह अच्छे विपक्ष की कमी है।' एक मजबूत विपक्ष की संभावना दिख रही है लेकिन केवल अनुभव ही बता सकता है कि क्या यह 'अच्छा विपक्ष' होगा?

सदन में संख्यात्मक रूप से बड़े विपक्ष के साथ राजकोष पक्ष को बेहतर प्रबंधकों की आवश्यकता हो सकती है जो सदन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सहजता से गलियारे में घूम सकें। दुख की बात है कि एक दशक की स्थिरता और पूर्वानुमानित राजनीति के बाद देश गठबंधन राजनीति की अनिश्चितता में फिर से प्रवेश कर रहा है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में देश को एन.डी.ए. गठबंधन द्वारा चलाया गया था, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त था।

भाजपा के 240 सीटों पर सिमटने से मौजूदा एन.डी.ए. गठबंधन पहले से अलग होगा। आशा की किरण यह है कि 1999-2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विपरीत जिसमें 182 भाजपा सदस्य थे और अन्य दलों के 115 सदस्यों पर निर्भर थे, यह वर्तमान एन.डी.ए. गठबंधन के अंकगणित में बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वपूर्ण सुधार एजैंडा अधिक दलों को उनका समर्थन करने के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे सरकार को अधिक स्थिरता मिलेगी।

इस चुनाव में सामने आई एक और गंभीर चुनौती अलगाववादी विचारधारा के प्रति निष्ठा रखने वाले कम से कम 3 स्वतंत्र उम्मीदवारों की जीत थी। उनमें से 2 अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा, पंजाब से जीते, जबकि तीसरे, अब्दुल राशिद शेख, उर्फ इंजीनियर राशिद, जम्मू-कश्मीर से चुने गए। आखिरी बार ऐसी अलगाववादी आवाज 1999 में भारतीय संसद में प्रवेश कर सकी थी जब सिमरनजीत सिंह मान ने पंजाब के संगरूर से चुनाव जीता था। पिछले 2 दशकों में अब तक ऐसी आवाजें राज्य विधानसभाओं तक ही सीमित थीं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. की तीसरी बार जीत एक संसदीय रिकॉर्ड होगी। हालांकि, स्थिति दोनों पक्षों की ओर से अधिक समायोजन और जिम्मेदार राजनीति की मांग करती है। महात्मा गांधी को कई बातों के लिए याद किया जाता है। लेकिन वह स्वतंत्रता-पूर्व युग में गठबंधन की राजनीति शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी सफलता विनम्रता और शिष्टता में निहित है, ऐसे गुण जिनकी भारतीय राजनीति को सख्त जरूरत है।-राम माधव (लेखक, इंडिया फाऊंडेशन के अध्यक्ष और आर.एस.एस. से जुड़े हैं)

मोदी 3.0 में कैसी होंगी गठबंधन सरकार की आर्थिक नीतियां, अर्थशास्त्रियों ने दिया यह जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मोदी 3 .0 में सुधारों की रफ्तार पहले की तरह बरकरार रहेगी। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे श्रम और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों में आर्थिक सुधार और नीति समीक्षा जारी रखने की जरूरत होगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि गठबंधन की राजनीति के कारण लोकलुभावन उपायों पर खर्च बढ़ सकता है।

नई दिल्ली। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) निर्वाचित नेता नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए भारत प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। एक दशक तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाने के बाद मोदी अब गठबंधन सरकार चलाएंगे। इसमें तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख भागीदार होंगे। हालांकि, गठबंधन के बावजूद विशेषज्ञों को लगता है कि नई सरकार के आर्थिक एजेंडे में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मोदी 3.0 में सुधारों की रफ्तार पहले की तरह बरकरार रहेगी और ये धीमे नहीं होंगे। साथ ही, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे, श्रम और विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों में आर्थिक सुधार और नीति समीक्षा जारी रखने की जरूरत होगी।

इंफ्रा पर जोर देने की जरूरत

चौदहवें वित्त आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के पूर्व निदेशक एम गोविंद राव ने कहा, 'सरकार 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए मार्केट में दूरगामी सुधार करने होंगे। अर्थव्यवस्था को खोलना और बुनियादी ढांचे के विकास जोर देना होगा। साथ ही, श्रम आधारित मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर रहना चाहिए।'

गोविंद राव ने कहा कि गठबंधन के माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार करना जाहिर तौर पर आसान नहीं होता, लेकिन सरकार का फोकस इन्हीं चीजों पर रहना चाहिए। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गठबंधन की राजनीति के कारण लोकलुभावन उपायों पर खर्च बढ़ सकता है। सरकार इंडिया सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। बुनियादी ढांचा और विनिर्माण जैसे क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता बने रहेंगे।

लोकलुभावन खर्च बढ़ेगा

लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिटायर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट और लेखक गौतम सेन ने कहा, 'अधिक लोकलुभावन व्यय की ओर झुकाव होने की संभावना है। गठबंधन सहयोगियों के राज्यों को अधिक संसाधन मिल सकते हैं। लेकिन भारत के सार्वजनिक वित्त की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है और आरबीआई से महत्वपूर्ण भंडार द्वारा इसे बढ़ाया जाएगा। भारत का बुनियादी ढांचा व्यय तेजी से जारी रहेगा, लेकिन शायद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अधिक रहेगी।'

बजट से पता चलेगा एजेंडा

जुलाई में घोषित होने वाले पूर्ण बजट में मोदी 3.0 के आर्थिक एजेंडे का पता चलेगा। कई अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि बजट में मुख्य रूप से किसानों और गरीबों के लिए कल्याण और सहायता योजनाओं में तेजी देखने को मिलेगी। बजट नई गठबंधन सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकताओं को इंगित करेगा और अगले पांच वर्षों के लिए विकास की दिशा तय करेगा।

हिमालयन मिनरल वाटर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू, यह है पूरा मामला

NCLT ने हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। LEEL इलेक्ट्रिकल्स के लिए दी गई कॉरपोरेट गारंटी में चूक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर बैंक ने एक याचिका दायर की थी जिसे ट्राइब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है। जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेय पदार्थों के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ 50 करोड़ रुपये के चूक का दावा किया था।

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। LEEL इलेक्ट्रिकल्स के लिए दी गई कॉरपोरेट गारंटी में चूक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर बैंक ने एक याचिका दायर की थी, जिसे ट्राइब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने देहरादून स्थित इस कंपनी की कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के लिए भूपेश गुप्ता को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) भी नियुक्त किया है।

NCLT ने दिवाला मामले पर क्या कहा

दो सदस्यों वाली पीठ ने पिछले सोमवार को दिए आदेश में कहा, 'हम इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक/वित्तीय ऋणदाता (जेएंडके बैंक) ने ऋण और चूक को साबित कर दिया है, जो कि निर्धारित सीमा से अधिक है। धारा 7 के तहत आवेदन कॉरपोरेट कर्जदार (हिमालयन मिनरल वाटर्स) के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए उपयुक्त पाया गया है।'

जम्मू और कश्मीर बैंक ने पेय पदार्थों के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ 50 करोड़ रुपये के चूक का दावा किया था। हिमालयन मिनिरल वाटर्स एलईईएल इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए कॉरपोरेट गारंटर थी।

हैवेल्स इंडिया को बेचा था कारोबार

एलईईएल इलेक्ट्रिकल्स ने मई 2017 में अपना कारोबार हैवेल्स इंडिया को 1,550 करोड़ रुपये में बेचा था। अप्रैल, 2020 में एलईईएल इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ एनसीएलटी द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू की गई थी, क्योंकि इसके एक सक्रिय कर्जदार ने याचिका दायर की थी। बाद में, खरीदार न मिलने पर एनसीएलटी ने दिसंबर 2021 में परिसमापन आदेश पारित किया।

एलईईएल इलेक्ट्रिकल्स पर एक्शन

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने करीब दो महीने पहले ने एलईईएल इलेक्ट्रिकल्स के प्रमोटर भरत राज पुंज और उनके छह पूर्व अधिकारियों पर 14.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी के खातों में गड़बड़ी और हेराफेरी के एक मामले में उन्हें प्रतिभूति बाजार से पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा, उन्हें तीन वर्षों तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत मध्यस्थ के साथ किसी भी भूमिका में जुड़ने से रोक दिया गया है।

पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में मशहूर हस्तियों का जमघट, अंबानी और अदाणी भी रहे मौजूद

अरबपति कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। मुकेश अंबानी के साथ राष्ट्रपति भवन में उनके बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद थे जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी। अदाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदाणी भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। आइए जानते हैं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हाल।

नई दिल्ली। एनडीए के निर्वाचित नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों के अलावा कई मशहूर हस्तियां भी मौजूद रहीं। इनमें तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ बिजनेसमैन भी शामिल थे। अरबपति कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। मुकेश अंबानी के साथ राष्ट्रपति भवन में उनके बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद थे, जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी।

वहीं, अदाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदाणी भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल आया था। हालांकि, रिजल्ट वाले दिन अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट भी दिखी।

पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में 7 देशों के नेताओं के नेता मौजूद रहे। देश के फिल्म स्टार भी इस समारोह में पहुंचे। इनमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, विक्रांत मेसी और राजकुमार हिरानी शामिल हैं। पीएम मोदी ने रविवार सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फिर वे अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि और नेशनल वॉर मेमोरियल गए थे। सुबह मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की थी।

पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में दिखी सांस रोक देने वाली हलचल, अब कैसा रहेगा मिजाज?

पिछले हफ्ते साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स 3.7 फीसदी के फायदे में रहा। वहीं निफ्टी 3.4 फीसदी मजबूत होकर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का एलान किया और उस फैसले से मार्केट खुशी से झूम गया। हालांकि उससे पहले शेयर मार्केट में काफी नाटकीय उतार-चढ़ाव वाला रहा। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते शेयर मार्केट में कैसी हलचल देखने को मिलेगी।

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में काफी नाटकीय उतार-चढ़ाव वाला रहा। एग्जिट पोल के बाद सेसेंक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन, जब लोकसभा चुनाव के असली नतीजे तो वे एग्जिट पोल से मेल नहीं खाए। लिहाजा, शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये डूब गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कुल मिलाकर कारोबारी हफ्ता बढ़त के साथ बंद हुआ। निवेशकों के नुकसान की भरपाई भी हो गई।

इस हफ्ते किन फैक्टर पर रहेगी नजर?

मोदी सरकार की वापसी का संकेत मिलने के बाद शेयर मार्केट ने गिरावट की भरपाई की थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद बाजार में फिर तेजी का दौर देखने को मिल सकता है।

शेयर मार्केट के मंत्रालय के बंटवारे पर भी नजर रहेगी। बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों को कौन-से मंत्रालय देती है। बाजार उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।

12 जून को औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे। फिर महंगाई से जुड़े डेटा भी आएंगे। 14 जून को आयात-निर्यात का आंकड़ा सामने आएगा। बाजार इन पर भी प्रतक्रिया दे सकता है।

फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजे शुक्रवार को सामने आएंगे। विदेशी निवेशकों के साथ भारतीय इन्वेस्टर्स की भी मीटिंग पर नजर रहेगी कि ब्याज दरों में कटौती पर क्या फैसला होता है।

पिछले हफ्ते कैसा रहा मार्केट का हाल?

पिछले हफ्ते साप्ताहिक आधार पर बीएसई सेंसेक्स 3.7 फीसदी के फायदे में रहा। वहीं, निफ्टी 3.4 फीसदी मजबूत होकर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का एलान किया और उस फैसले से शेयर मार्केट खुशी से झूम गया। सेंसेक्स 1,618.85 अंक (2.16 फीसदी) और एनएसई निफ्टी 468.75 अंक (2.05 फीसदी) मजबूत होकर 23,290.15 अंक पर बंद हुआ।

रियल एस्टेट सेक्टर को मोदी 3.0 से बड़ी उम्मीदें, घटेंगे या बढ़ेंगे घरों के दाम?

आज (रविवार 9 जून) मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया था उसमें किफायती हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला था क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम PMAY-अर्बन के तहत 2 करोड़ से अधिक मकान जोड़े गए थे। ऐसे में इंडस्ट्री को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं।

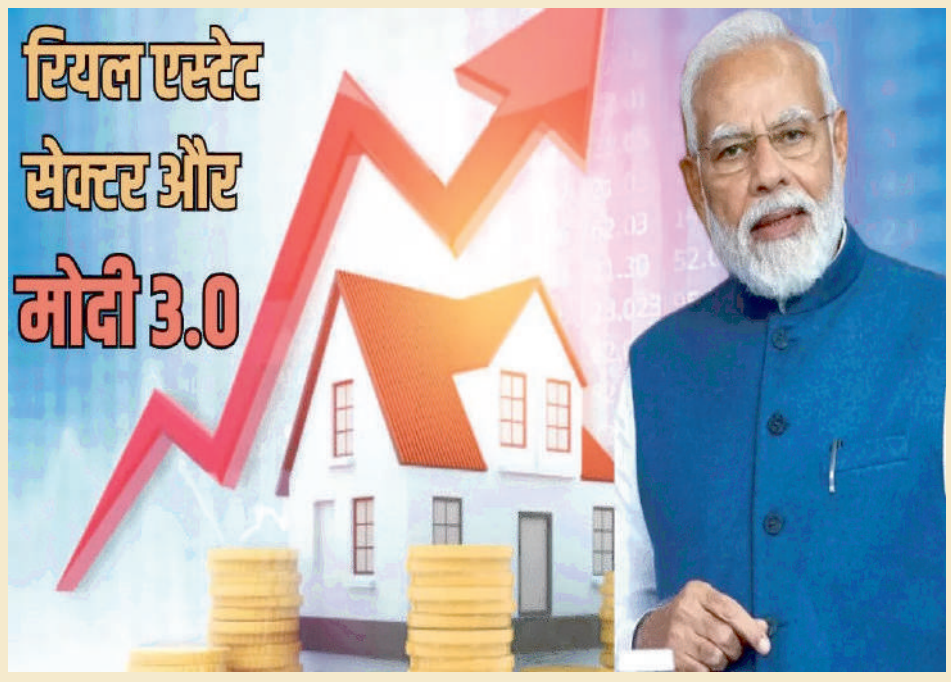

नई दिल्ली। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पर है। पिछले 10 साल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक मकान बनवाए।

आज (रविवार, 9 जून) मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को पीएम मोदी से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया था, उसमें किफायती हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला था, क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम PMAY-अर्बन के तहत 2 करोड़ से अधिक मकान जोड़े गए थे।

रियल एस्टेट इंडस्ट्री की डिमांड

एक्सपर्ट का अनुमान है कि देश का रियल एस्टेट मार्केट 2040 तक 65,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। ऐसे में इंडस्ट्री का कहना है कि उन्हें अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सरकार से लगातार मदद की दरकार होगी।

नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) के चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी का कहना है, 'इकोनॉमिक परफॉरमेंस इंडिकेटर्स को बूस्ट करने के लिए पॉलिसी और स्कीम में आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। PMAY को भी लगातार बढ़ावा देना होगा। सरकार को टैक्स और जीएसटी को ज्यादा तर्कसंगत बनाना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि अप्रूवल, डेवलपमेंट प्रीमियम और स्टाम्प ड्यूटी जैसी चीजों की लागत भी कम करने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। हीरानंदानी ने जोर दिया कि अगर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना है, तो जमीन और वित्तीय मंजूरी में गैरजरूरी अड़चनों को दूर करना होगा।

जीएसटी में सुधार की मांग

इंडस्ट्री एक्सपर्ट लगातार सरकार से रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने की मांग कर रहे हैं। इनमें से अहम डिमांड जीएसटी में सुधार से जुड़ी है। सीबीआरई के चेयरपर्सन और सीईओ अंशुमान मैगजीन ने कहा, 'सरकार को निर्माण में लगने वाले कच्चे माल की लागत कम करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही, किफायती आवास की परिभाषा को नए सिरे से भी तय करने की जरूरत है। कच्चे माल और श्रम समेत निर्माण की लागत काफी बढ़ी है और उसी हिसाब से किफायती आवास का दोबारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।'

केंद्रीय बजट 2023-24 में, वित्त मंत्रालय ने पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपये (9.64 अरब डॉलर) की घोषणा की थी। एक साल पहले के मुकाबले इसमें 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

बढ़ रहा रियल एस्टेट सेक्टर

भारत के रिटेल, हॉस्पिटिलैटी और कर्मशियल रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये सभी देश की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हैं। वित्त वर्ष 2023 में भारत के आवासीय संपत्ति बाजार में घरों की बिक्री 3.47 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, बिक्री के वॉल्यूम में भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें सालाना आधार पर 36 प्रतिशत का इजाफा हुआ और कुल 3,79,095 यूनिट बिकीं।

सेबी के फैसले से बढ़ेगा निवेश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) प्लेटफॉर्म के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है, जो सभी प्रकार के निवेशकों को भारतीय रियल एस्टेट बाजार में निवेश करने की अनुमति देगा। इससे आने वाले वर्षों में भारतीय बाजार में 1.25 ट्रिलियन का निवेश होने का अनुमान है।

डोसा, इडली खाना होगा महंगा? इंस्टेंट आटा मिक्स पर लगेगा 5 की जगह 18 फीसदी जीएसटी...

गुजरात की किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी एडवांस्ड अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ अपील की थी। किचन एक्सप्रेस का कहना था कि उसके सात इंस्टेंट आटा मिक्स रेडी टु ईट नहीं हैं क्योंकि उन्हें कुछ खाना पकाने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई और अब इन प्रोडक्ट पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगी।

नई दिल्ली। इडली, डोसा और खमण कई लोगों का पसंदीदा नाश्ता और भोजन है। लेकिन, अब इनका स्वाद लेना थोड़ा महंगा हो सकता है। दरअसल, इडली, डोसा और खमण बनाने में इस्तेमाल होने वाले इंस्टेंट आटा मिक्स पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पर एक अहम स्पष्टीकरण आया है। अब यह तय हो गया कि इंस्टेंट आटा मिक्स पर 5 नहीं बल्कि 18 फीसदी का टैक्स लगेगा।

यह फैसला गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग (GAAAR) ने फैसला सुनाया है। उसका कहना है कि इडली, डोसा और खमण में इस्तेमाल होने वाले आटे समेत इंस्टेंट मिक्स को छतुआ या सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

गुजरात की किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी एडवांस्ड अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ AAAR के पास गया था। किचन एक्सप्रेस का कहना था कि उसके सात 'इंस्टेंट आटा मिक्स' 'रेडी टु ईट ' नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खाना पकाने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में उन्हें 'रेडी टु कुक' कहा जा सकता है। कंपनी गोटा, खमण, दालवाड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के आटे के मिश्रण को पाउडर के रूप में बेचती है।

किचन एक्सप्रेस की दलील थी कि यह सत्तू के समान है और इस पर 5 प्रतिशत का माल और सेवा कर (जीएसटी) लगना चाहिए। लेकिन, GAAAR ने उसकी दलील को खारिज कर दिया। उसने कहा कि 'इंस्टेंट आटा मिक्स' बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उचित जीएसटी नियमों के तहत कवर नहीं होती है, जैसा कि सत्तू के मामले में है।

GAAAR ने क्या कहा?

CBIC के परिपत्र के अनुसार, सत्तू बनाने के लिए मिलाई जाने वाली सामग्री की छोटी मात्रा को जीएसटी नियमों में 5 प्रतिशत कर दर के लिए पात्र माना गया है। GAAAR ने कहा, हालांकि, यह स्पष्टीकरण मौजूदा मामले में लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलकर्ता जिन प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहा है, उनमें मसाले के साथ अन्य सामग्री भी शामिल हैं। यह चीज 'सत्तू' के मामले में नहीं होती।"

अपीलेट अथॉरिटी ने यह भी कहा कि अंतिम उपभोक्ता को इंस्टेंट मिक्स आटे को पकाने के लिए कुछ तैयारी करनी होती है। लेकिन, सिर्फ यही एक फैक्टर इस बात का आधार नहीं हो सकता कि इंस्टेंट मिक्स आटे पर 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए।

सफेद कुर्ता-चूड़ीदार पजामा, नीली जैकट... नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तीसरी बार शपथ लेने के दौरान चूड़ीदार पायजामे के साथ सफेद कुर्ता और नीली जैकेट पहनना पसंद किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने अपनी पोशाक के साथ काले जूते पहने। मोदी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब उन्होंने क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा और हल्के सुनहरे रंग की जैकेट पहनी थी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार शपथ लेने के दौरान चूड़ीदार पायजामे के साथ सफेद कुर्ता और नीली जैकेट पहनना पसंद किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने अपनी पोशाक के साथ काले जूते पहने।

मोदी ने 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने क्रीम रंग का कुर्ता-पायजामा और हल्के सुनहरे रंग की जैकेट पहनी थी। वर्ष 2019 के शपथ ग्रहण के दौरान भी मोदी ने लगभग ऐसी ही पोशाक का चयन किया था।

महत्वपूर्ण अवसरों पर मोदी की पसंदीदा पोशाक कुर्ता और बंद गला जैकेट है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान वह आकर्षक और रंग-बिरंगी पगड़ी पहने हुए भी नजर आए हैं। पीएम मोदी ने इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुरंगी बंधानी ¨प्रट वाला साफा पहना था।

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, अदाणी;

फिल्म अभिनेता शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा डडलानी के साथ आए। अभिनेता अक्षय कुमार रवीना टंडन अनुपम खेर और विक्रांत मैसी भी समारोह में शामिल हुए। रजनीकांत अपनी पत्नी लता के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने चेन्नई से आए। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। वह मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई देते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लगातार तीसरी बार निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एकतरफ मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी जैसे बड़े उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल हुए, वहीं शाह रुख खान, अक्षय कुमार और नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत जैसी फिल्मी हस्तियां भी उपस्थित रहीं।

राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रविवार शाम को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी अपने दोनों बेटों अनंत और आकाश के अलावा अपने दामाद आनंद पीरामल के साथ मौजूद रहे। गौतम अदाणी अपनी पत्नी प्रीति और भाई राजेश अदाणी के साथ आए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी अपनी पत्नी के साथ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रतिभा पाटिल भी मौजूद रहीं।

फिल्म अभिनेता शाहरुख अपनी मैनेजर पूजा डडलानी के साथ आए। अभिनेता अक्षय कुमार, रवीना टंडन, अनुपम खेर और विक्रांत मैसी भी समारोह में शामिल हुए। रजनीकांत अपनी पत्नी लता के साथ इस कार्यक्रम में

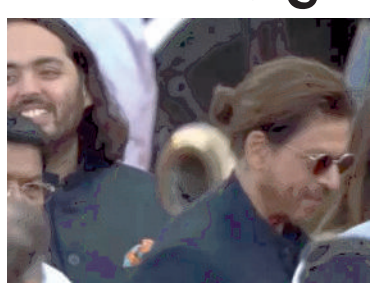

शामिल होने चेन्नई से आए। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है। वह मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई देते हैं।

इससे कुछ घंटे पहले अनुपम खेर ने कहा कि उन्हें लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में जाने का अवसर मिला है। यह बहुत खास और बड़ा अवसर है कि लगातार तीनों समारोहों में प्रधानमंत्री भी मोदी ही रहे हैं। उनका डायलाग भी वही रहेगा 'मैं नरेन्द्र दामोदरदास मोदी..जय हो, जय हिंद।

उन्होंने 'एक्स' पर निमंत्रण पत्र भी साझा किया। मंडी से सांसद कंगना रनौत भी समारोह में उपस्थित रहीं और उन्होंने अपनी तैयारियों की कई स्टोरी इंस्टाग्राम पर साझा कीं। अभिनेता और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण अपनी रूसी पत्नी अना लेजनेवा के साथ शामिल हुए। भोजपुरी सिनेस्टार व भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। अभिनेता अजय देवगन, राजकुमार राव और कांतारा फेम के ऋषभ शेट्टी ने मोदी को इंटरनेट मीडिया पर शुभकामनाएं दीं।

मोदी 3.0 मंत्रीमंडल

कैबिनेट मंत्री.....

1. नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री
2. राजनाथ सिंह, मंत्री
3. अमित अनिल चन्द्र शाह, मंत्री
4. नितिन रमेश गडकरी, मंत्री
5. जगत प्रकाश नड्डा, मंत्री
6. शिवराज सिंह चौहान, मंत्री
7. निर्मला सीतारमन, मंत्री
8. डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, मंत्री
9. मनोहर लाल (खट्टर), मंत्री
10. एचडी कुमार स्वामी, मंत्री
11. पीयूष वेदप्रकाश गोयल, मंत्री
12. धर्मेन्द्र प्रधान, मंत्री
13. जीतन राम मांझी, मंत्री
14. राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री
15. सर्वानंद सोनोवाल, मंत्री
16. डॉ. वीरेंद्र कुमार, मंत्री
17. किंजनप्पू राम मोहन नायडू, मंत्री
18. प्रहलाद वेंकटेश जोशी, मंत्री
19. जुएल ओरांव, मंत्री
20. गिरिराज सिंह, मंत्री
21. अश्विनी वैष्णव, मंत्री
22. ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मंत्री
23. भूपेंद्र यादव, मंत्री
24. गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री
25. अन्नपूर्णा देवी, मंत्री
26. किरन रिजिजू, मंत्री
27. हरदीप सिंह पुरी, मंत्री
28. डॉ. मनसुख मांडविया, मंत्री
29. गंगापुरम किशन रेड्डी, मंत्री
30. चिराग पासवान, मंत्री
31. सीआर पाटिल, मंत्री

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)...

32. इंद्रजीत सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
33. डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
34. अर्जुन राम मेघवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
35. प्रताप राव गनपत राव जाधव, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
36. जयंत चौधरी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री.....

37. जितिन प्रसाद, राज्यमंत्री
38. श्रीपाद येशो नाइक, राज्यमंत्री
39. पंकज चौधरी, राज्यमंत्री
40. कृष्ण पाल, राज्यमंत्री
41. रामदास आठवले, राज्यमंत्री
42. रामनाथ ठाकुर, राज्यमंत्री
43. नित्यानंद राय, राज्यमंत्री
44. अनुप्रिया पटेल, राज्यमंत्री
45. वी सोमन्ना, राज्यमंत्री
46. पेम्मासानी चंद्रशेखर
47. प्रो. एसपी सिंह बघेल, राज्यमंत्री
48. शोभा करंदलाजे, राज्यमंत्री
49. कीर्ति वर्धन सिंह, राज्यमंत्री
50. बीएल वर्मा, राज्यमंत्री
51. शांतनु ठाकुर, राज्यमंत्री
52. सुरेश गोपी, राज्यमंत्री
53. डॉ. एल मुरुगन, राज्यमंत्री
54. अजय टमटा, राज्यमंत्री
55. बंडी संजय कुमार, राज्यमंत्री
56. कमलेश पासवान, राज्यमंत्री
57. भागीरथ चौधरी, राज्यमंत्री
58. सतीश चंद्र दुबे, राज्यमंत्री
59. संजय सेठ, राज्यमंत्री (रांची से भाजपा सांसद)
60. रवनीत सिंह, राज्यमंत्री
61. दुर्गादास उईके, राज्यमंत्री
62. रक्षा निखिल खड़से, राज्यमंत्री
63. सुकांतो मजूमदार, राज्यमंत्री
64. सावित्री ठाकुर, राज्यमंत्री
65. तोखन साहू, राज्यमंत्री
66. डॉ. राज भूषण चौधरी, राज्यमंत्री
67. भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा, राज्यमंत्री
68. हर्ष मल्होत्रा, राज्यमंत्री
69. नीमूबेन बम्भाणीया, राज्यमंत्री
70. मुरलीधर मोहोल, राज्यमंत्री
71. जार्ज कुरियन, राज्यमंत्री
72. पवित्र मार्गरीटा, राज्यमंत्री

मोदी सरकार में जेपी नड्डा की हुई वापसी, कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में शामिल हुए. कैबिनेट में शामिल होने के बाद निश्चित ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा. लेकिन सवाल उठता है कि नड्डा के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? जगत प्रकाश नड्डा 2020 से बीजेपी अध्यक्ष हैं. वे राज्यसभा सदस्य हैं. नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं. 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं. नड्डा के कैबिनेट में जाने से बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर हलचल शुरू हो गई है. कल तक कुछ नाम सामने आ रहे थे- इनमें भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख थे. लेकिन भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल और धर्मेंद्र प्रधान ने भी मोदी कैबिनेट में शपथ ले ली. इसलिए ये सभी लोग भी रेस से बाहर हो गए हैं।

ओड़िशा मे बीजेपी सरकार आने के बाद IAS ऑफिसर और बिजेड़ी नेता इस्तफा और सन्यास का बड़ी कतार लगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : ओडिशा खादी और ग्रामीण उद्यम बोर्ड के अध्यक्ष संग्राम केशरी पाइकराय ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आईएमएसएमई विभाग को भेज दिया है । मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में वे 2 बार अध्यक्ष पद पर रहे। पहली बार 31 अगस्त 2019 से 5 जून 2022 तक सेवा दी गई ।बिजेड़ी नेता और पूर्व सांसद अच्युत सामंत ने प्रत्यक्ष राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की । कल बीजे सुप्रीमो ने नवीन पटनायक से मुलाकात की । लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उन्हें मौका देने के लिए आभार व्यक्त किया । हालांकि अच्युत ने कहा कि प्रत्यक्ष राजनीति से संन्यास लेने के बाद वह समाज सेवा में सक्रिय रहेंगे ।पांडियन ने किया बड़ा ऐलान । पांडियन ने एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की । बीजू जनता पार्टी की हार के

लिए माफी मांगने के साथ ही पांडियन ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की ।

बीजे की हार के बाद पांडियन ने पहली बार अपना मुंह खोला है । एक वीडियो संदेश में हत्योदी ने बीजू के परिवार से माफ़ी मांगी । उन्होंने कहा, 'मैं एक छोटे से गांव और अच्छे परिवार से हूं। हमेशा लोगों के लिए काम किया । मैं 12 साल से भी कम समय पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में शामिल हुआ था। मैं नवीन का समर्थन करने के लिए राजनीति में आया। मुख्यमंत्री के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है । प्रभु की कृपा से जनसेवा में सफलता मिली। हम नवीन के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे । पिता की संपत्ति के अलावा कोई संपत्ति नहीं है ।

'विनम्र रहें और ईमानदारी से समझौता न करें', मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत

उन्होंने कहा टीम के रूप में और टीम भावना से काम कीजिए और...आप ईमानदारी और पारदर्शिता से समझौता नहीं कर सकते। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब से यह परंपरा बन गई है कि मोदी मंत्रिपरिषद के गठन से पहले नेताओं को चाय पर बुलाते हैं उनसे चर्चा करते हैं और उन्हें सलाह के साथ-साथ नसीहत भी देते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी नवगठित सरकार के सभी मंत्रियों को रविवार को नसीहत दी कि उन्हें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि आम लोग यही पसंद करते हैं। साथ ही मोदी ने उन्हें ईमानदारी एवं पारदर्शिता से कभी कोई समझौता न करने की भी सलाह दी।

सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण से पहले नामित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान मोदी ने कहा कि लोगों की उनसे काफी अपेक्षाएं हैं और सभी को इन्हें पूरा करना होगा। उन्होंने निवर्तमान मंत्रिपरिषद के कई वरिष्ठ नेताओं और नए नामित मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, ₹आपको जो भी काम सौंपा जाएगा, उसे ईमानदारी से करें और विनम्र रहें क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं जो विनम्र होते हैं।"

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे यह भी कहा कि वे सभी सांसदों को आदर व सम्मान दें चाहे वे किसी भी पार्टी के हों क्योंकि उनमें से सभी को लोगों ने चुना है। मोदी ने कहा कि मंत्रियों को हमेशा विनम्र होना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का भी सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "टीम के रूप में और टीम भावना से काम कीजिए और ...आप ईमानदारी और पारदर्शिता से समझौता नहीं कर सकते।' गौरतलब है कि वर्ष 2014 में मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से यह परंपरा बन गई है कि मोदी मंत्रिपरिषद के गठन से पहले नेताओं को चाय पर बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उन्हें सलाह के साथ-साथ नसीहत भी देते हैं।

बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी, इस काम के लिए भारत से मांगी मदद

भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी को दुनियाभर से बड़ी हस्तियों से बधाईयां मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है। बिल गेट्स ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीतने पर बधाई।

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पद की शपथ (PM Modi Oath Ceremony) ली। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति भवन में हुए एक भव्य कार्यक्रम में 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनियता की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी को दुनियाभर से बड़ी हस्तियों से बधाईयां मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है।

नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीतने पर बधाई- गेट्स

बिल गेट्स ने एक्स पर ट्वीट करके कहा, ₹नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीतने पर बधाई। आपने स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर साझेदारी की उम्मीद है।"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023